A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 07 जुलाई, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 305, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर पर सरकार इतनी चिंतित क्यों है?

वृंदा तुल्सयान

यूजरनेम फीचर विवाद अब बड़ा होता दिख रहा है। मेटा के मालिकाना हक वाले व्हाट्सएप ने सोमवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस फीचर का ऐलान किया। गुरुवार तक सरकार ने सिर्फ मेटा (Meta) ही नहीं, बल्कि टेलीग्राम (Telegram) और सिग्नल (Signal) को भी ऐसे ही फीचर्स को लेकर नोटिस भेज दिए। यह मामला अब इस बात की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बन गया है कि नई दिल्ली किसी निजी मैसेजिंग ऐप के नए फीचर्स पर कितना नियंत्रण रख सकती है।

व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड कुणाल शाह ने इस फीचर को 'ज्यादा प्राइवेसी के साथ जुड़ने का तरीका' बताया। इस फीचर के जरिए व्हाट्सएप पर दो लोग बिना एक-दूसरे का फोन नंबर देखे आपस में चैट कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह फीचर वैकल्पिक होगा। अनजान लोग किसी का यूजरनेम खोज नहीं सकेंगे। यूजर चाहें तो एक अतिरिक्त 'यूजरनेम की' भी चालू कर सकते हैं। ऐसे में चैट शुरू करने के लिए यूजरनेम और यह की, दोनों की जरूरत होगी।

पहली नजर में यह फीचर बहुत मामूली लग सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि दूसरे मैसेजिंग एप्स में पहले से ऐसे फीचर मौजूद हैं। लेकिन भारत में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स वाले व्हाट्सएप के लिए, जो उसका सबसे बड़ा बाजार है, यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। और ऐसी सरकार के लिए, जिसने पिछले एक साल में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी निगरानी बढ़ाई है, यह फीचर बेहद संवेदनशील समय पर आया है।

यही वजह है कि प्राइवेसी देने वाले इस फीचर और उस सरकार के बीच टकराव, जो ऐसे फीचर्स को लेकर पहले से सतर्क है, व्हाट्सएप के यूजरनेम को न्यूज़मेकर ऑफ दि वीक बनाता है। बुधवार को आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के भारत में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नोटिस भेजा। इसमें मेटा से कहा गया कि वह इस फीचर की शुरुआत रोक दे और तीन दिन के भीतर इसका जवाब दे. मंत्रालय ने कहा कि धोखाधड़ी को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो नियामकीय कार्रवाई की जाएगी। अगले ही दिन Signal और Telegram को भी नोटिस भेजे गए। उनसे पूछा गया कि उनके यहां पहले से मौजूद बिना फोन नंबर वाले मैसेजिंग फीचर में धोखाधड़ी रोकने के क्या इंतजाम हैं।

अब डिजिटल अधिकारों से जुड़े संगठन सरकार के इस कदम का विरोध करने लगे हैं। वहीं अलग-अलग मैसेजिंग ऐप्स की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही। दरअसल भारत में फोन नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं होता। यह बैंक खाते, PI ID और किसी व्यक्ति की डिजिटल जिंदगी के बड़े हिस्से से जुड़ा होता है। व्हाट्सएप पर किसी नए ग्रुप में जुड़ने की कीमत लंबे समय से अपना फोन नंबर सबको दिखाना रही है। फोन नंबर साझा किए बिना चैट करने की सुविधा यूजर को उसकी बाकी डिजिटल पहचान से थोड़ा अलग रहने का मौका देती है।

इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट से जुड़े टेक्नोलॉजी पॉलिसी वकील ध्रुव गर्ग ने कहा, 'व्हाट्सएप पर यूजरनेम आपको सिर्फ मेटा के सिस्टम तक सीमित रखता है। एक यूजरनेम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखा जा सकता है, लेकिन उससे बाहर नहीं। जबकि फोन नंबर हर जगह इस्तेमाल होता है। हालांकि यह सिर्फ फोन नंबर के ऊपर एक अतिरिक्त सुरक्षा परत है, उसका विकल्प नहीं।

सरकार ने इसी फीचर को अपराध की नई संभावना के रूप में देखा। उसकी सबसे बड़ी चिंता किसी और की पहचान बनाकर धोखा देने की है। ऐसे देश में जहां पहले से डिजिटल अरेस्ट स्कैम और फिशिंग के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार को डर है कि बैंक, मंत्रालय या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर लोगों को ठगा जा सकता है। मेटा को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि यह फीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और फर्जी पहचान वाले मामलों को 'काफी बढ़ा सकता है।' कंपनी को तीन दिन में जवाब देने को कहा गया। MeitY के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'डरना व्हाट्सएप को चाहिए, हमें नहीं।'

सबसे बड़ी चिंता यही है कि फोन नंबर की तुलना में किसी यूजरनेम की नकल करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसकी असली पुष्टि सिर्फ प्लेटफॉर्म ही कर सकता है। गुरुवार को जारी FAQ में व्हाट्सएप ने कहा कि उसने पहले ही सार्वजनिक हस्तियों, मशहूर लोगों, सरकारी संस्थाओं और मेटा-वेरिफ़ाइड अकाउंट्स के यूजरनेम और उनसे मिलते-जुलते दूसरे यूजरनेम भी रिजर्व कर लिए हैं, ताकि उन्हें सिर्फ असली मालिक ही इस्तेमाल कर सकें। कंपनी ने इस दावे को 'गलत' बताया कि लोकप्रिय यूजरनेम किसी और ने पहले ही ले लिए हैं। इसके बाद सरकार की जांच और बढ़ गई। टेलीग्राम से यह भी पूछा गया कि उसे यह फीचर रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। टेलीग्राम और सिग्नल ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अब मामला सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि व्हाट्सएप फर्जी पहचान बनाने वालों को रोक पाएगा या आम यूजर की सुरक्षा कर पाएगा। एक हफ्ता पहले तक यूजरनेम सिर्फ एक छोटा सा फीचर था। आज यह इस बात की परीक्षा बन गया है कि दिल्ली किसी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले उसमें कितनी दखल दे सकती है। यहीं से कानूनी सवाल शुरू होता है। धोखाधड़ी को लेकर सरकार की चिंता से सहमत कुछ लोग भी उसके कदम पर सवाल उठा रहे हैं।

इंटरनेट फ्रीडम फ़ाउंडेशन ने कहा है कि इस नोटिस का कानून में कोई साफ आधार नहीं है। कार्यपालिका बिना किसी कानूनी अधिकार के ऐसे वैध फीचर्स को रोक रही है, और उनके साथ उन निजी बातचीतों को भी सीमित कर रही है, जिनकी सुरक्षा ये फीचर करते हैं। '

इसी तरह सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने भी सरकार से नोटिस वापस लेने, उन्हें सार्वजनिक करने और यह बताने की मांग की कि यह कार्रवाई किस कानून के तहत की गई। आपत्ति यह है कि कार्यपालिका बिना किसी स्पष्ट कानून के यह तय कर रही है कि कोई निजी कंपनी कौन-सा फीचर बना सकती है और कौन-सा नहीं। सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया उस प्लेटफॉर्म से आई, जिसे सरकार ने कोई नोटिस ही नहीं भेजा था। Zoho की बनाई भारतीय मैसेजिंग ऐप ,rattai, जिसे लंबे समय से व्हाट्सएप के स्वदेशी विकल्प के रूप में पेश किया जाता रहा है, पहले से लोगों को फोन नंबर की जगह यूजरनेम से जुड़ने की सुविधा देती है। किसी भी तरह का नोटिस मिलने से पहले ही, Zoho के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने X पर घोषणा की कि कंपनी यह फीचर बंद कर देगी।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

'अर्थव्यवस्था' ने फिर से पकड़ी रफ्तार

- कच्चे तेल की कीमत गिरते ही भारत की बल्ले-बल्ले
- रिपोर्ट में दावा-भारतीय रुपए पर कम हो गया है दबाव
- ईरान शांति समझौते के बाद इकोनॉमी को मिली है गति

नई दिल्ली (एजेंसी)। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) की निकासी में कमी और रुपये में निवेश वाली परिसंपत्तियों के आकर्षक मूल्यांकन के चलते भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति और विकास की संभावनाएं पहले से अधिक मजबूत हुई हैं। यह बात डीएसपी की एक नई रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगे भी आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने वाली नीतियां अपनाने की संभावना रखता है। पर्याप्त तरलता बनाए रखने से बॉन्ड यील्ड में समय के साथ गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में फिलहाल अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है और मांग में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत के ग्रोथ आउटलुक में आगे और सुधार की संभावना है। डीएसपी का मानना है कि बेहतर आर्थिक वृद्धि,कॉरपोरेट भारत की बिक्री में तेजी लाने का काम करेगी।

अर्थव्यवस्था में दिख रही मजबूती

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट अब अर्थव्यवस्था की एक बड़ी मजबूती बन सकता है। इसे पहले बाजार के लिए चिंता का विषय माना जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार रुपये में निवेश वाली परिसंपत्तियों पर बेहतर रिटर्न, रुपये का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (आरईईआर) अत्यधिक आकर्षक स्तर पर होना, बड़ी कंपनियों के शेयरों का कम मूल्यांकन और एफपीआई के डेट निवेश में बढ़ोतरी जैसे कारकों ने भारत की व्यापक आर्थिक तस्वीर को मजबूत बनाया है।

भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की सीएम मोहन यादव ने रखी नींव

राज्य सरकार इसी माह, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में है अग्रसर : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करते हुए

- **मुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि**

कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे सम्मान के साथ मनाई जा रही है। डॉ. मुखर्जी के एक देश-एक विधान-एक निशान-एक प्रधान के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में अग्रसर है।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत ने विश्व में बनाई विशेष पहचान- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए विश्व में विशेष पहचान बनाई है। डॉ. मुखर्जी ने देश और समाज के सर्वांगीण विकास की कल्पना की। राज्य सरकार ने डॉ. मुखर्जी की जयंती के अवसर पर 15 दिवसीय जनकल्याण पखवाड़े की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गरीब, जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

हर क्षेत्र में तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार बना दिल्ली में बना भारत मंडपम् हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। डॉ. मुखर्जी की जयंती पर आज भोपाल के सतगढ़ी में मध्यप्रदेश के सबसे बडे कन्वेंशन सेंटर और सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी जा रही है। राज्य सरकार कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर तैयार कर रही है, जिसकी क्षमता 5 हजार सीट्स की रहेगी। सतगढ़ी में बनने वाले नए विशाल कन्वेंशन सेंटर में 10 हजार से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था है। भोपाल सबसे समृद्ध और सशक्त राजधानी बनने जा रहा है। हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है।

अब मध्यप्रदेश की धरती पर बनेंगे, रक्षा क्षेत्र के उपकरण, मिसाइल और हथियार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने रक्षा क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। अब रक्षा क्षेत्र के कई उपकरण, मिसाइल और हथियार मध्यप्रदेश की धरती पर बनेंगे। चंबल की धरती सालों से मां भारती की सेवा करने वाले वीर सैनिकों की भूमि रही है। अब यहां आधुनिक हथियार भी तैयार किए जाएंगे। यह मिसाइल एक हजार किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने की क्षमता वाली होंगी। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री रवीन्द्र यति, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

यूपी का जलालाबाद अब हुआ परशुराम पुरी

- योगी सरकार ने बदला शाहजहांपुर के कस्बे का नाम

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुराम पुरी करने का प्रस्ताव पास हो गया है। नाम परिवर्तन के इस प्रक्रिया की शुरुआत मार्च 2018 से हुई थी। यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली मानी जाती है। यहां भगवान परशुराम का एक प्राचीन मंदिर भी है। शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद ने मार्च 2018 और सितंबर 2023 में बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया। शाहजहांपुर के तत्कालीन डीएम ने अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा था। प्रदेश सरकार ने इसे केंद्र सरकार को आगे भेज दिया था। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त, 2025 को राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे थी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी : चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर

- पूर्व IFS कृष्ण मोहन नए महासचिव, ट्रस्ट बोला- घटना से हम शर्मिंदा

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक 3 घंटे चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बोले महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। चंपत राय ने कहा है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ वह कष्टदायी है। इससे हम सब दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। ट्रस्टी के. पाराशरन ने कहा था कि त्यागपत्र देते ही इसे स्वीकार करना ट्रस्ट के संविधान में हैं। इसलिए इस्तीफा स्वीकार किया गया। चंपत राय की अनुपस्थिति में नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है।

भारी बारिश से एमपी-महाराष्ट्र में त्राहिमाम

- सतारा में पुल टूटा, क्रेन से निकाली गईं कारें
- बालाघाट जिले में नदी में बहे कार व जेसीबी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई-पुणे रेल रूट पर करजत-लोनावला के भोर घाट सेक्शन में दो जगह लैंडस्लाइड हो गई। इससे तीनों रेलवे लाइनें प्रभावित हो गईं। 20 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। उधर, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। सातारा जिले के महाबलेश्वर में वेण्णा नदी का पुल टूटने से 10-12 पर्यटक फंस गए। कारों को क्रेन की मदद से निकाला गया। डीएम ने आज सभी सरकारी और प्रायवेट स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है। मुंबई एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट रद्द हुईं। मुंबई में प्राइवेट ऑफिसों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गई। 6-7 गाड़ियां मलबे में दब गईं। मलबा हटाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से 14 साल की लड़की की मौत हो गई।

कुल्लू में पागल नाले में बाढ़,मलबा आने से हाईवे बंद- हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सुबह से हो रही बारिश के बाद आज पागल नाला में बाढ़ आ गई। इससे सारा मलबा हाईवे पर आ गया। इसके बाद लारजी को सैंज से जोड़ने वाला हाईवे वाहनों के लिए बंद हो गया है। मुबंई में लगातार बारिश हो रही है।

बालाघाट में नदी में बहे कार-जेसीबी- मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। बालाघाट से आए वीडियो में किरनापुर-लांजी से होकर बहने वाली बाघ नदी में कार, जेसीबी और लोडर जैसी गाड़ियां बहती दिखीं। जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सीमा से लगी बाघ नदी पर पुल बनाया जा रहा है। तकरीबन 150 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1017.24 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ा तो निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को बहा ले गया। डिंडौरी में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते नर्मदा सहित सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। तुडार नदी में पुलिया के ऊपर पानी बह रहा है, इससे करंजिया ब्लॉक के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है।

सुप्रभात

दिन ढले
मजूर स्त्रियों की आंख में
उतर आता है घर और पल्लू में
गांठ लगा सरपट भागती है वे
अभावों के पहाड़ लाँघते हुए
थकी शाम
निर्जन एकांत या भीड़ भरी सड़कों पर
उन्हें भय नहीं होता
हरदम
व्यस्त होती है वे
जीवन के अनसुलझे धागे सुलझाने में
बेचैन होती है वे
बच्चों की भूख पर और
सहलाती है पीठ हवा की
वे पेट भर अनाज,स्वाद भर गुड़
और डिबरी भर तेल के लिए
टटोलती है पल्लू बार-बार!
सचमुच
योद्धा होती हैं वे
नही सोचती अपनी थकान..बीमारी
या मृत्यु के बारे में,
अनवरत लड़ते हुए युद्ध
दुखों को पिरोती है गीतों में
यादों में
मजूर स्त्रियों के
बहुत कुछ चला जाता है साथ
मगर,नही रहती शेष मजूर स्त्रियां
किसी की यादों में!

-सुरेश शर्मा, मनासा

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 07 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

इंडोनेशिया में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, जेट ने किया एस्कॉर्ट

राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ अगवानी की,भव्य स्वागत किया गया

जकार्ता (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी के एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट किया। इसके बाद एयरपोर्ट पहुंचने पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने प्रोटोकॉल तोड़ पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी तीन दिन इंडोनेशिया में रहेंगे।

● **भारत-इंडोनेशिया रक्षा संबंध होंगे मजबूत-** भारत के रक्षा और सुरक्षा सहयोग में उच्च स्तरीय दौरा, नियमित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एक्सरसाइज और रक्षा उद्योग में गहरे सहयोग (ब्रह्मोस की बिक्री सहित) के जरिए तेजी आई है और इसका दायरा भी बढ़ा है। समुद्री पड़ोसी होने के नाते, दोनों देशों ने 2018 में हिंद-प्रशांत में भारत-इंडोनेशिया समुद्री सहयोग के साझा दृष्टिकोण को अपनाया। आईएफसी-आईओआर में एक इंडोनेशियन लाइजन ऑफीसर की तैनाती से हमारी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को और बढ़ावा मिलेगा। भारत एनडीए और डीएसएससी में इंडोनेशियन कैडेट्स और ऑफीसर्स के लिए स्लॉट भी तय करेगा, जिससे रक्षा के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी।

● **व्यापार और निवेश पर भी बनेगी बात-** इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश के जरिए विकास को बढ़ावा देना है। विकसित भारत 2047 और एमास (गोल्डन) इंडोनेशिया 2045 के डेवलपमेंट विजन के बीच मजबूत तालमेल है। इंडोनेशिया, आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है, जिसका 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 24.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।

पाकिस्तान देखता रह गया भारत ने मार लिया मैदान!

पीएम मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़नी तय है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे क्षेत्र में खुद को इस्लामी देशों का अगुवा मानता है। वहीं, यह दौरा चीन को भी अखर सकता है, क्योंकि चीन इंडोनेशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इंडोनेशिया के बेहद करीब मलक्का स्ट्रेट से ही चीन के ज्यादातर समुद्री जहाज गुजरते हैं।

इंडोनेशिया को ब्रह्मोस देगा! दुश्मन की उड़ी नींद

भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडोनेशिया से अपने रिश्ते तेजी से बढ़ा रहा है। खासतौर पर पीएम मोदी के कार्यकाल में रक्षा और समुद्री भागीदारी को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत इंडोनेशिया के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए हाई लेवल दौरे, नियमित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास और गहरे रक्षा सहयोग को बढ़ा रहा है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बिक्री भी शामिल है। पीएम मोदी के दौरे में इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को लेकर डील हो सकती है।

संक्षिप्त समाचार

मेरे कहने के बाद भी नहीं हो रहा काम

● जेडीयू दफ्तर में अचानक उखड़ गए नीतिश कुमार!

पटना (एजेंसी)। नीतिश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को काम में लापरवाही पर पकड़ लिया। दरअसल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष

नीतिश कुमार अपने औचक निरीक्षणों के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को अचानक जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए, जिससे वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हड़कंप मच गया। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे नीतिश कुमार ने पूरे कार्यालय का जायजा लिया और संगठन के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान कामों में लापरवाही और देरी देखकर नीतिश कुमार का पारा चढ़ गया।

चन्नी-वड़िंग की लड़ाई कांग्रेस को पड़ रही भारी

● पंजाब में चुनाव से पहले ही संकट में फंसी पार्टी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब कांग्रेस एक बार फिर उसी दौर से गुजरती दिखाई दे रही है, जिसने 2021 में पार्टी को गहरे राजनीतिक संकट में डाल दिया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चली लंबी खींचतान ने कांग्रेस की सरकार को कमजोर कर दिया था। अब 2026 में हालात फिर कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार

राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस एक बार फिर अपनी पुरानी गलतियां दोहराने जा रही है।

दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई- पंजाब कांग्रेस में संगठन के हालिया पुनर्गठन के बाद असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक लगातार संगठन में बदलाव और नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मोरिंडा स्थित चन्नी के आवास पर पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक ने यह संकेत दिया कि पार्टी के भीतर एक मजबूत असंतुष्ट खेमा सक्रिय हो चुका है। दूसरी ओर, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। **2021 में भी इसी दौर से गुजरी थी कांग्रेस-** मौजूदा घटनाक्रम काफी हद तक 2021 की परिस्थितियों से मेल खाता है। उस समय भी पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर लंबी

मप्र के मछली उत्पादन को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान : मुख्यमंत्री

प्रदेश के किसानों और मछुआरा समुदाय को मिलेगा प्रोत्साहन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाता की समृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से किसान कल्याण वर्ष में प्रदेश में पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित या बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में तालाबों और जलाशयों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अन्नदाता की समृद्धि के लिए कृषि के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं विकसित हो रही हैं। प्रदेश के मछुआरा समुदाय के लोग मछली पालन जरिए ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इन सबकी बेहतरी के लिए मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के अंतर्गत गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दिया जा रहा है। आज कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच हुआ एग्रीमेंट प्रदेश में मत्स्य पालन और मछुआ कल्याण के क्षेत्र में नया इतिहास रचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की

उपस्थिति में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी- ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच, प्रदेश में 7 हजार 430 करोड़ रुपए के निवेश और बाय बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। यह एग्रीमेंट मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एग्रीमेंट पर हुए हस्ताक्षर के बाद यह विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा तथा कुवैत फिश ट्रेड यूनियन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री फारेस बौकम्माज़ उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में है मत्स्य पालन क्षेत्र में अपार संभावनाएं- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन विकास के लिए पर्याप्त जलसंरचनाओं के भंडार हैं। इससे देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि और खाद्यान्न के विकास को लेकर मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। कुवैत हमारा मित्र देश है, प्रदेश में विदेशी निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार पूर्ण समर्पण के साथ तेजी से कार्य कर रही है, अब इसके सुखद परिणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। भविष्य में मध्यप्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में हुए एग्रीमेंट के दौरान जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026 के अंतर्गत राज्य में आधुनिक निर्यातोन्मुखी एवं मूल्य संवर्धन मत्स्य उद्योग के विकास के लिए निजी एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रावधान है। अनुबंध के अंतर्गत 7 हजार 430 करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर सहित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

कूनो अभयारण्य बना रहेगा चीता लांचिंग का ग्राउंड

● दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे अब और चीते

नौरादेही और बन्नी क्षेत्र नए चीता ठिकाने बनेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रोजेक्ट चीता की सफलता से उत्साहित दक्षिण अफ्रीका अब भारत को और चीते देने को राजी हो गया है। इसके तहत जल्द ही छह से आठ और चीते लाए जा सकते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई चर्चा में बनी सहमति के बाद चीतों की नई खेप को कूनो में रखने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वैसे भी कूनो में बाहर से आने वाले चीतों को रखने के लिए जो ढांचा तैयार किया है, भविष्य की चिंता है।

● **राजस्थान ने भी मांगे हैं चीते-** चीतों को बसाने को लेकर अकेले मध्य प्रदेश और गुजरात ही नहीं, बल्कि राजस्थान भी रुचि दिखा रहा है। सरिस्का में आयोजित एक सम्मेलन में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने यह मांग रखी और कहा कि वह भी अपने यहां चीतों को बसाना चाहते हैं। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत राजस्थान के मुकुंदरा, शाहगढ़ व भैंस रोडगढ़ अभयारण्य को चीतों के लिए उपयुक्त पाया गया था। वैसे भी कूनो से चीते निकलकर लगातार राजस्थान की सीमा में दाखिल हो रहे हैं।

जगदीश देवड़ा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से किया संवाद

कार्यकर्ताओं से संवाद कर जनसमस्याओं का किया त्वरित समाधान

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया।

मध्यप्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिन जनसमस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका, उन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी जनसमस्याओं को समझा और उन्हें शीघ्र समाधान दिलाने का आश्वासन दिया।

आज प्रेम पर लिखा जाना सबसे अधिक आवश्यक : दुबे

देवास, भावेश कानूनगो। आज के समय में प्रेम पर लिखा जाना सबसे अधिक आवश्यक है। जो प्रेम हमारे भीतर से धीरे-धीरे रिक्त होता जा रहा है, उसे कविता में स्थान मिलना चाहिए। एक युवा कवि को प्रेम पर अवश्य लिखना चाहिए, किंतु उसका प्रेम कृत्रिम या सतही नहीं, बल्कि सच्चा और संवेदनशील होना चाहिए।

यह बात प्रतिष्ठित कवि आशुतोष दुबे ने मध्यप्रदेश साहित्य सम्मेलन की देवास इकाई एवं लिटरेचर क्लब के संयुक्त तत्वावधान में देवास में 'कविता का 'कल'' विषय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कही। मुख्य वक्ता कवि एवं अनुवादक रतन चौहान ने कहा कि कविता का 'कल' आश्वस्त करता है। उन्होंने युवा कविता के तेवरों पर चर्चा करते हुए कहा कि उसमें चिंता भी है, जीवन-संघर्ष भी और अपने समय के समाज को पहचानने की गहरी समझ भी। उन्होंने डब्ल्यू. एच. ऑडन तथा टी. एस. एलियट जैसे कवियों का संदर्भ देते हुए समकालीन कविता के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि चित्रकला, साहित्य, संगीत और लोकसंगीत जैसी कलाओं को अलग-अलग दृष्टि से नहीं, बल्कि समग्र रूप में देखा जाना चाहिए।

साहित्यकार आशीष दशोत्तर ने कहा कि छोटे शहरों, जैसे रतलाम, देवास, सीहोर, मंदसौर और नीमच से अनेक उभरते हुए साहित्यकारों की नई पौध तैयार हो रही है। इन कस्बों के साहित्यकार किसी भी बड़े शहर के साहित्यकारों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं हैं। कुछ समर्पित लोग इन कस्बों में लगातार बेहतर साहित्यिक आयोजन कर समाज को प्रेरित और लाभान्वित कर रहे हैं। सीहोर जैसे कस्बे में 'साहित्य समागम' तथा देवास-रतलाम जैसे नगरों में देशभर के प्रतिष्ठित आयोजन एवं 'सुने-सुनाएँ' तथा 'लिटरेचर क्लब' की स्थानीय गोष्ठियों के माध्यम से नए लेखकों को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य बखूबी किया जा रहा है। कथाकार एवं उपन्यासकार पंकज सुबीर ने कहा कि लेखक कभी मरता नहीं, वह अपनी रचनाओं में जीवित रहता है। उन्होंने युवा कवि शहरयार पर चर्चा करते हुए कहा कि किसी प्रकाशक का लेखक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी वह लेखन की प्रसव-पीड़ा और लेखक की बेचैनी को सही अर्थों में समझ सकता है। उन्होंने कहा कि शहरयार पिछले सात-आठ वर्षों से शिवना प्रकाशन का कार्य संभाल रहे हैं। जैसे चंदन घिसने वाले के हाथों में उसकी सुगंध बस जाती है, उसी प्रकार उन्हें विश्वास था कि शहरयार भी एक दिन उत्कृष्ट साहित्य का सृजन अवश्य करेंगे। कविता का 'कल' विषय पर युवा कवि अमेय कांत के कविता संग्रह 'किसी छूटे हुए दिन में' तथा शहरयार के नए कविता-संग्रह 'पुराना मौसम लौटा' के बहाने सार्थक बातचीत हुई। इसमें समकालीन कविता के साथ-साथ कविता के भविष्य पर विमर्श हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दोनों युवा कवियों अमेय कांत (देवास) एवं शहरयार (सीहोर) के काव्य-पाठ से हुआ। अमेय कांत के कवि बनने तक की यात्रा को उनके सहयात्री मनीष शर्मा ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत प्रकाश कांत, शशिकांत यादव, अजय पंडित, हिमांशु कुमावत, चयन कानूनगो, कैलाश वर्मा, नरेंद्र जोशी, भावेश कानूनगो, अनार सिंह ठाकुर, सुरेंद्र सैंधव, संजय आचार्य तथा अमित पिठवे ने किया।

हाफिज सईद ने रची थी पहलगाम हमले की साजिश

● एनआईए ने स्पेशल कोर्ट दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ● एजेंसी ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में उसे हमले की साजिश रचने, आतंकियों को संचालित करने और भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोपी बनाया गया है। एनआईए ने हाफिज सईद को व्यक्तिगत तौर पर भी आरोपी बनाया है। उसे प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख बताया गया है। चार्जशीट में उसके खिलाफ यूएपीए की कई धाराएं लगाई गई हैं। एनआईए ने कहा कि

यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले दाखिल 1,597 पन्नों की चार्जशीट का हिस्सा है। एनआईए ने 15 दिसंबर 2025 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर साजिद जट समेत 6 आतंकियों को आरोपी बनाया था।

एनआईए चार्जशीट में क्या-क्या खुलासा - हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा आतंकी सैफुल्लाह उर्फ सैफुल्लाह साजिद जट्ट उर्फ लंगड़ा था। साजिद, पाकिस्तान के लाहौर में कसूर में रहता है। साजिद जट्ट ही आतंकियों का मेन हैंडलर था। वह उन्हें रियल टाइम डायरेक्शन दे रहा था। उसने ही हमले वाली जगह बैसरन वैली की लोकेशन भेजी थी। हमले के दौरान भी वह लगातार आतंकियों से बात कर रहा था। एनआईए चार्जशीट के मुताबिक टूरिस्ट गाइड परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार वक्त रहते जानकारी देते तो हमला को टाला जा सकता था। दोनों गाइड ने आतंकियों को बैसरन में देखा था लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बताया। दोनों गाइड्स गिरफ्तार हो चुके हैं। हमले से एक दिन पहले तीनों आतंकियों ने गाइड परवेज की झोपड़ी में मदद मांग कर खाना खाया।

● **पहलगाम हमले के 3 गुनहगार ढेर हो चुके-** एनआईए के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में शामिल पाक आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान भाई और हमजा अफगानी को सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई, 2025 को ढेर कर दिया था। भारत के टॉप वांटेड में शामिल आतंकी लंगड़ा पर 10 लाख का इनाम है। इन्हीं के पास से गो-प्रो कैमरा मिला था। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए 6-7 मई की रात 1.05 बजे पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारत ने 24 मिसाइलें दागीं थीं। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए।

वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य, मुस्लिमों का प्रदर्शन

कहा-हमने कभी अयोध्या-मथुरा की कमेटियों में जगह नहीं मांगी, सारंग बोले-धर्म के चश्मे से न देखें

भोपाल (नप्र)। देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों की नियुक्ति हुई है। मध्यप्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघौगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव को सदस्य बनाया है। सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के विरोध में सोमवार को भोपाल के बुधवारा चौराहे पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित नहीं

ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि वक्फ मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक संस्था है, जहां लोग अपनी संपत्ति अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित नहीं है। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन दो दिन पहले हुआ है, जिसमें पहली बार दो गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों को शामिल किया गया है। कमेटी इसी नियुक्ति का विरोध कर रही है। शमशुल हसन ने अयोध्या, सोमनाथ और मथुरा की धार्मिक संस्थाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि जब मुस्लिम समाज ने कभी उन संस्थाओं के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की, तो वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की जरूरत क्यों महसूस की गई।

कांग्रेस विधायक मसूद बोले- मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा

वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी, जो सनव्वर पटेल को इतनी जल्दबाजी करनी पड़ी। मध्य प्रदेश शासन ने एक और गलती की है। दो अन्य समाज के लोगों को रखने का प्रावधान है, शासन ने तीन रख दिए। आयुक्त भी अन्य कास्ट के हैं।

जल्दबाजी में वक्फ बोर्ड के गठन का आरोप

शमशुल हसन ने अयोध्या, सोमनाथ और मथुरा की धार्मिक संस्थाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि जब मुस्लिम समाज ने कभी उन संस्थाओं के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की, तो वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की जरूरत क्यों महसूस की गई। शमशुल हसन ने आरोप लगाया कि नए कानून के लागू होने के तुरंत बाद जल्दबाजी में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति करनी थी, तो मुस्लिम समाज के योग्य और अनुभवी लोगों, जैसे सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी।

'वक्फ की जमीन मुल्ला-मौलवी की नहीं; हिंदुस्तान की है' : विधायक रामेश्वर शर्मा

मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है। सनवर पटेल को फिर से इसका अध्यक्ष बनाया गया है। पहली बार वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को जगह मिली है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा प्रहार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन तो हिंदुस्तान की है। सब लोग गंगा-जमुनी तहजीब की बात करते हैं, यह देश की संस्कृति में है। वह गरीबों को दी जाने वाली भूमि है। वक्फ की जमीनें किसी मुल्ला और मौलवी के नाम नहीं की गई है। सरकार गरीबी रेखा कार्ड बना रही है। आयुष्मान कार्ड बना रही है। वक्फ संसोधन बिल के बाद उसमें दो हिंदू सदस्य बने हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वक्फ के हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने के लिए होगा। इसलिए उनको वहां रखा गया है। इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ की बात नहीं है। हां, इससे उनको तकलीफ जरूर होगी, जो वक्फ की संपत्ति को खा रहे थे।

बिजली कंपनी फैसला- जिस ठेकेदार के नाम पर कार्य आदेश, वही करेगा काम

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने लाइन एवं सबस्टेशन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिस पैनलबद्ध (Empanelled) ठेकेदार के नाम पर कार्य आदेश (Purchase Order) जारी किया गया है, वही संबंधित कार्य करेगा। किसी भी स्थिति में वह कार्य किसी अन्य ठेकेदार, एजेंसी या व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकेगा।

कंपनी के संज्ञान में आया था कि कुछ स्थानों पर कार्य आदेश एक ठेकेदार के नाम पर जारी होने के बावजूद काम किसी अन्य व्यक्ति या ठेकेदार से कराया जा रहा था। इसे कंपनी ने नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है। जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य केवल अधिकृत ठेकेदार द्वारा ही किया जाए। इसके लिए नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण भी किया जाएगा।

यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि कार्य किसी अन्य व्यक्ति या ठेकेदार से कराया जा रहा है, तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार का कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता है, उसे भविष्य के कार्यों से वंचित किया जा सकता है, सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है तथा आवश्यकता होने पर ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। कंपनी ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पांच वर्षीय कार्यकाल कल होगा पूरा

नए राज्यपाल को लेकर बढ़ी चर्चाएं, मुख्यमंत्री ने लोकभवन पहुंच की मुलाकात, आज दिल्ली जाएंगे सीएम

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पांच वर्षीय कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो रहा है। हालांकि, राष्ट्रपति भवन की ओर से अब तक उनके कार्यकाल के विस्तार या नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में नए राज्यपाल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

इधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और उनके रात में वहीं रुकने का कार्यक्रम है। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति सहित अन्य राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 29 जून को लोक भवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की थी। इसके बाद 2 जुलाई को संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी राज्यपाल से भेंट की थी। इसी बीच दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार के चयन को लेकर भी मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास के दौरान चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

गर्भ रखना या नहीं, महिला को निर्णय लेने का अधिकार

इंदौर हाईकोर्ट का दंपत्ति के बीच चल रहे विवाद में फैसला; कहा- पति की सहमति जरूरी नहीं

इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर गर्भावस्था है तो महिला खुद तय कर सकती है कि वह गर्भ रखना चाहती है या नहीं। उसे गर्भपात के लिए पति की सहमति आवश्यक नहीं है।

29 जून 2026 को कोर्ट ने यह आदेश दिया था। मामला इंदौर संभाग के एक हाई प्रोफाइल दंपती का है। शादी को दो साल हुए थे। इस बीच दोनों में विवाद होने लगे। खास बात यह कि इसी दौरान पत्नी गर्भवती थी। उसे 13 हफ्ते का गर्भ था।

चूंकि दंपत्ति के बीच विवाद ज्यादा होने लगे और पत्नी भी अलग हो गई। ऐसी स्थिति में पत्नी नहीं चाहती थी कि बच्चा जन्म ले क्योंकि मौजूदा विकट स्थिति और उसके भविष्य का सवाल था।

ई-अटेंडेंस लगाने की जल्दी में शिक्षक का एक्सीडेंट

प्राचार्य को चिट्ठी लिखकर कहा- स्कूल आने की जल्दी में हुई दुर्घटना, एबसेंट न लगाएं

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में लागू की जा रही ई-अटेंडेंस व्यवस्था के बीच एक शिक्षक हादसे का शिकार हो गए। स्कूल समय पर पहुंचकर ई-अटेंडेंस लगाने की जल्दबाजी में उनकी बाइक बारिश के कारण फिसल गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। शिक्षक ने प्राचार्य को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें अनुपस्थित न माना जाए, क्योंकि वे विद्यालय पहुंचने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इधर, इस घटना के बाद शिक्षक संगठनों ने ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं।

रामपुर घाटी में फिसली बाइक, आंख में हुआ ब्लड क्लॉट

घायल शिक्षक पूरनचंद्र सोनी मुरैना जिले के सबलगढ़ विकासखंड के बामसौली के रहने वाले हैं। उन्होंने प्राचार्य को लिखे पत्र में बताया कि 2 जुलाई को बारिश के बावजूद वे ई-अटेंडेंस में अनुपस्थित न लगने के डर से जल्दी-जल्दी स्कूल जा रहे थे। रास्ते में रामपुर घाटी में सड़क फिसलन भरी होने के कारण उनकी बाइक फिसल गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद राहगीरों और स्कूल स्टाफ ने उन्हें सबलगढ़ अस्पताल पहुंचाया। जांच में शरीर पर कई चोटों के साथ आंख में ब्लड क्लॉट होने की पुष्टि हुई। उन्होंने पत्र में आग्रह किया है कि दुर्घटना को देखते हुए उन्हें अनुपस्थित दर्ज न किया जाए।

एमपी ट्रांसको की 593 ईएचवी लाइनों ने बनाया चार वर्षों से बिना ब्रेकडाउन के बिजली पारेषण का उल्लेखनीय कीर्तिमान : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल (नप्र)। आंधी-तूफान, तेज बारिश, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक चुनौतियों और अन्य अप्रत्याशित व्यवधानों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) की 593 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) ट्रांसमिशन लाइनों ने पिछले चार वर्षों (करीब 1500 दिन) से बिना किसी ब्रेकडाउन के निर्बाध विद्युत पारेषण का उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे विद्युत पारेषण व्यवस्था की विश्वसनीयता और मजबूती प्रमाणित हुई है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कंपनी के अभियंताओं, तकनीकी कर्मचारियों तथा ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस में संलग्न आउटसोर्स कर्मियों की प्रतिबद्धता, दक्षता और टीमवर्क का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन लाइनों की इस उपलब्धि के पीछे सतत एवं सजग मेंटेनेंस, प्रभावी मॉनिटरिंग तथा अभियंताओं, तकनीकी कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों की निरंतर तत्परता प्रमुख कारण रहा है।

आधुनिक तकनीक और नवाचार के इस्तेमाल से मिली सफलता

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रदेश में विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क को अधिक विश्वसनीय एवं सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीकों के उपयोग, विभिन्न नवाचार, नियमित मेंटेनेंस, समयबद्ध निरीक्षण तथा प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में ईएचवी लाइनें लंबे समय से बिना किसी ब्रेकडाउन के सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। साथ ही इस उपलब्धि के पीछे ट्रांसमिशन लाइनों की नियमित पेट्रोलिंग, थर्मो-विजन निरीक्षण, संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी, प्री-मानसून मेंटेनेंस अभियान तथा एससीएडीए आधारित सतत मॉनिटरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बालाघाट में नदी में बहे कार-जेसीबी, डिंडौरी में घरों में घुसा पानी, गृहस्थी बही

भिंड-डिंडोरी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, 57 किमी की रफ्तार से आंधी, अगले 48 घंटे डेंजर अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। बालाघाट से आए वीडियो में किरनापुर-लांजी से होकर बहने वाली बाघ नदी में कार, जेसीबी और लोडर जैसी गाड़ियां बहती दिखीं।

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सीमा से लगी बाघ नदी पर पुल बनाया जा रहा है। तकरीबन 150 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1017.24 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ा तो निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को बहा ले गया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भिंड के रोन में सर्वाधिक 134 मिमी बारिश हुई।भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने मिलकर पूरे प्रदेश में भारी तबाही और राहत का माहौल एक साथ बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे पूरे मध्य प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं। डिंडौरी में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते नर्मदा सहित सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। तुडार नदी में पुलिया के ऊपर पानी बह रहा है, इससे करंजिया ब्लॉक के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। 11 मकानों में पानी घुसने से गृहस्थी का सामान भी बह गया।

मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के 23 जिलों में आज अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट है। सोमवार को सागर, दमोह, बैतूल, देवास, आलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, आगर-मालवा, राजगढ़ और भोपाल में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

आज से राष्ट्रीय संस्कृत रूपक-निर्देशन कार्यशाला

देशभर के 12 राज्यों के प्रतिभागी लेंगे प्रशिक्षण, नाट्यशास्त्र के व्यावहारिक पक्षों को जानेंगे

भोपाल (नप्र)। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में संस्कृत रंगमंच को नई पीढ़ी से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 7 से 27 जुलाई तक 21 दिवसीय संस्कृत रूपक-निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। नाट्यशास्त्र अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ 7 जुलाई को सुबह 10:30 बजे परिसर के भवभूति सभागार में होगा।

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात संस्कृतविद् एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी होंगे। सारस्वत अतिथि के रूप में संगीत नाटक अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक गिरिशन वी. सोपानम् तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिनेत्री रीता वर्मा मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोपाल परिसर के निदेशक प्रो. हंसधर झा करेंगे, जबकि भारतीय भाषा, साहित्य एवं संस्कृति संकायाध्यक्ष प्रो. सनन्दन कुमार त्रिपाठी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय स्तर की इस कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के लगभग 12 राज्यों से चयनित प्रतिभागी संस्कृत नाट्य-निर्देशन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कार्यशाला में अभिनय, मंच-संयोजन, चरित्र-प्रस्तुति, प्रकाश व्यवस्था तथा नाट्यशास्त्र के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण देने वाले विशेषज्ञों में मुंबई के संजीव परमार, जयपुर के प्रो. रामकुमार शर्मा, दीपक भारद्वाज, श्रृंगेरी के डॉ. राघवेंद्र भट्ट, उमेश तरकसवार और अल्पना वाजपेयी सहित देश के प्रतिष्ठित रंगकर्मी एवं विद्वान शामिल हैं।

विश्वविद्यालय के अनुसार कार्यशाला का उद्देश्य संस्कृत रंगपरंपरा को समकालीन रंगभाषा और प्रयोगधर्मिता से जोड़ते हुए नई पीढ़ी के रंगकर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि संस्कृत नाट्य परंपरा को आधुनिक मंचीय स्वरूप के साथ आगे बढ़ाया जा सके। कार्यशाला के समन्वयक प्रो. कृपाशंकर शर्मा एवं सह-समन्वयक डॉ. संगीता गुंदेचा हैं। भोपाल परिसर के निदेशक प्रो. हंसधर झा ने शहर के रंगकर्मियों, साहित्यकारों, कलाकारों, संस्कृत अध्येताओं एवं विद्यार्थियों से उद्घाटन समारोह में सहभागी बनने की अपील की है।

हरित भारत का संकल्प- ब्रह्माकुमारीज़ का सतत वृक्षारोपण एवं नशामुक्ति अभियान

वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत लगातार तीसरे दिन हुआ वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के साथ नशामुक्ति का भी लिया संकल्प

भोपाल। वन महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुख-शांति भवन, नीलबड़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 'वरिष्ठ राजयोगिनी बीके आर्किटेक्ट दुर्गा दीदी, बीके उर्मी दीदी, बीके हेमा बहन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके रामकुमार जी' के साथ 'हॉकी इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तोमर जी' तथा 'भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विवेक शर्मा जी' विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।

अपने उद्बोधन में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तोमर जी ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। प्रत्येक नागरिक यदि एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

वहीं श्री विवेक शर्मा जी ने कहा कि स्वस्थ समाज का

निर्माण तभी संभव है जब हम प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ नशामुक्ति को भी जनआंदोलन बनाएं। पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों का विकास राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष केवल प्रकृति की शोभा नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। वे हमें प्राणवायु, शुद्ध वातावरण, वर्षा, जैव विविधता तथा संतुलित जलवायु प्रदान करते हैं। आज जब पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह केवल एक पौधा लगाए ही नहीं, बल्कि उसके संरक्षण का भी संकल्प ले।

ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत पिछले दिनों विभिन्न स्थानों पर लगातार वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से समाज में पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता तथा भावी पीढ़ियों के लिए हरित एवं स्वस्थ वातावरण बनाने का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नशामुक्त भारत के निर्माण का भी आह्वान किया गया। उपस्थित सभी भाई-बहनों एवं अतिथियों ने नशामुक्त रहने, दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने तथा स्वस्थ, संस्कारित एवं मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने की प्रतिज्ञा ली।

अंत में सभी ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लेते हुए संदेश दिया कि जब प्रकृति सुरक्षित होगी, तभी मानवता का भविष्य सुरक्षित होगा।

संपादकीय

तीजनबाई : जाना विलक्षण कलाकार का

प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई का जाना पंडवानी जैसी छत्तीसगढ़ की लोककला को बुलंदी पर ले जाने वाली असाधारण कलाकार का जाना है। नागरी समाज के लिए अल्पज्ञात इस कला को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कला जगत उनका हमेशा ऋणी रहेगा। पद्मविभूषण और मानद डॉक्टरेट से सम्मानित तीजनबाई ने एम्स रायपुर में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। वे 70 वर्ष की थीं। तीजनबाई उस पारधी समाज से आती थीं, जिसे अंग्रेजों ने जरायमपेशा जाति घोषित कर रखा था। पंडवानी गायन उन्होंने अपने दादाजी से सीखा। उनका जन्म भिलाई के गनियारी गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही पंडवानी गायन शुरू कर दिया था। यूं पंडवानी गायक और भी रहे हैं, लेकिन तीजनबाई ने महाभारत की कथाओं को अपनी दमदार आवाज, अभिनय और अनूठी प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत कर लोक कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। अपने लंबे कलात्मक सफ़र में उन्होंने देश और विदेश में अनेक प्रस्तुतियां दीं। लोक कला में उनके अनूठे योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चूंकि उनका जन्म छत्तीसगढ़ के पाटन अटारी गांव में आठ अगस्त 1956 को लोकपर्व तीज के दिन हुआ था, इसलिए माता-पिता ने उनका नाम 'तीजन' रख दिया। तीजन की मां का नाम सुखवती देवी और उनके पिता का नाम हुनुकलाल पारधी था। तीजन अपने माता-पिता की पहली संतान थीं। उनका बचपन गंभीर अभाव में गुज़रा। पशु-पक्षियों के कलरव, माँ के लोकगीत और पिता के बांसुरी वादन ने नन्हीं तीजन बाई को प्रभावित किया। एक दिन उन्होंने अपने वृद्ध नाना को पंडवानी गाते हुए सुना तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसी समय उन्होंने पंडवानी सीखने का फ़ैसला कर लिया। हालांकि तीजनबाई उस पारधी समुदाय से थीं, जो जंगल में शिकार करके तथा पशु-पक्षियों को पकड़कर बेचने का काम करता है। लेकिन तीजनबाई ने शिकार के बजाए सृजन का रास्ता चुना। अपने शिकारी माहौल से निकल कर तीजन बाई ने पंडवानी के ज़रिए दुनियाभर में अपनी पहचान कायम की। वो कहा करती थीं कि मैं महाभारत करती नहीं, महाभारत की कथा सुनाती हूं। तीजन बाई ने 13 साल की उम्र में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। हालांकि इसी वजह से उनकी शादी भी टूट गई। लेकिन तीजनबाई ने इसकी चिंता नहीं की, वो कला के पथ पर आगे बढ़ती गईं। दरअसल छत्तीसगढ़ की पारधी और देवार जैसी आदिवासी जातियां 'पंडवानी' का गायन करती हैं। इसमें सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित महाभारत को आधार बनाकर पांडवों की कथा का गायन, अभिनय के साथ होता है। पंडवानी में एक मुख्य कलाकार होता है जो महाभारत की कथा सुनाता है और प्रसंग के हिसाब से कथा गायन के दौरान आने वाले पात्रों का अभिनय भी करता है। मुख्य कलाकार के साथ पांच से छह साथी कलाकारों की मंडली और एक रागी होता है जो हुंकार लगाता है, सवाल पूछता है और ज़रूरत के हिसाब से बीच-बीच में मुख्य कलाकार के साथ गाता भी है। तीजनबाई पंडवानी गायन की कापालिक शैली में गाती थी। वो छग की पहली महिला कलाकार थीं, जिन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया था।

धारावाहिक 'भारत एक खोज' में महाभारत प्रसंग के लिए आमंत्रित किया। इस तरह तीजन बाई की कला घर-घर तक पहुंची। उनकी प्रतिभा को देखते हुए भिलाई स्टील प्लांट ने उन्हें साल 1986 में नौकरी दी। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले। खास बात यह है कि तीजनबाई स्वयं बहुत ही खुद पढ़-लिख नहीं पाईं लेकिन साक्षरता अभियान और स्त्री अधिकार से जुड़े कार्यक्रमों में उन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। वे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थीं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

नजरिया

अंशुमान
लेखक संसद टीवी से सम्बद्ध पत्रकार हैं।

वैश्विक सहयोग को आधार दे रही भारत की ऊर्जा नीति

विश्व अर्थव्यवस्था आज एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। पिछले तीन दशकों तक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर विकसित देशों का दबदबा रहा, लेकिन अब यह संतुलन धीरे-धीरे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर खिसक रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अब केवल वैश्विक विकास में भागीदारी नहीं कर रहे, बल्कि उसकी दिशा और गति दोनों तय कर रहे हैं। इन देशों के विशाल और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उद्योगों को नई ऊर्जा दे रहे हैं। वहीं, इनकी बढ़ती विनिर्माण क्षमता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विविध और मजबूत बना रही है। स्थानीय उद्यमिता भी अब छोटे स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि वह वित्त, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक मानक स्थापित कर रही है।

वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं रह गया है कि क्या उभरती अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास का नेतृत्व करेंगी, बल्कि यह प्रवृत्ति अब लगभग तय मानी जा सकती है। असली सवाल यह है कि क्या ये देश उस नेतृत्व को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए मजबूत आर्थिक, संस्थागत और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ऊर्जा किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। उद्योगों का संचालन, कृषि का आधुनिकीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि इन सबकी नींव ऊर्जा पर ही टिकी है। आज ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन या तेल आयात का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का मूल आधार बन चुकी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के अनुसार आने वाले वर्षों में वैश्विक बिजली मांग में होने वाली लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आएगी। तेज़ औद्योगीकरण, शहरीकरण और डिजिटल विस्तार इस मांग को और बढ़ाएँगे। यह स्थिति विकास के बड़े अवसर भी देगी, लेकिन साथ ही ऊर्जा ढांचे पर भारी दबाव भी डालेगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो देश अपनी ऊर्जा प्रणाली को समय रहते मजबूत नहीं करेंगे, वे आर्थिक विकास की इस दौड़ में पिछड़ सकते हैं।

इस वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरती है क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले एक दशक में देश ने डिजिटल परिवर्तन, आधारभूत संरचना के विस्तार, स्टार्टअप क्रांति और विनिर्माण क्षेत्र में जो गति हासिल की है, उसने भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक विकास के एक मजबूत इंजन के रूप में स्थापित किया है। आज दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी भारत को केवल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन, अनुसंधान और दीर्घकालिक निवेश के केंद्र के रूप में देख रही है। वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम गति शक्ति, PLI योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों ने भारत की औद्योगिक क्षमता को नई दशा के साथ नई दिशा भी दी है।

इन सभी उपलब्धियों की असली नींव एक मजबूत और भरोसेमंद ऊर्जा व्यवस्था ही है। अगर किसी देश में ऊर्जा की सप्लाई अस्थिर हो, कीमतें लगातार बदलती रहें या वह बहुत ज्यादा दूसरे देशों से आयात पर निर्भर हो, तो उसका सीधा असर उद्योगों, रोजगार और आर्थिक विकास पर पड़ता है। उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, निवेशकों का भरोसा कम हो जाता है और विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसी कारण आज ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे आर्थिक ढांचे की रीढ़ बन चुकी है।

भारत जैसे बड़े और तेजी से विकसित होते देश के लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसमें और तेज़ी आने की संभावना है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में बिजली की मांग हर साल लगभग 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह वृद्धि केवल जनसंख्या बढ़ने के कारण नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण होंगे जैसे तेजी से फैलता हुआ औद्योगिक क्षेत्र, नए-नए डेटा सेंटरों का निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार।

इसके अलावा शहरों का तेजी से बढ़ना, लोगों की जीवनशैली में बदलाव और तकनीक पर बढ़ती निर्भरता भी बिजली की मांग को और बढ़ाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ऊर्जा की जरूरत सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर क्षेत्र चाहे वह उद्योग हो, परिवहन हो या सूचना प्रौद्योगिकी ऊर्जा पर और अधिक निर्भर होगा। इसका अर्थ साफ है कि भारत को केवल अधिक ऊर्जा नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा व्यवस्था चाहिए जो निरंतर उपलब्ध हो, किफायती हो, विविध स्रोतों पर आधारित हो और संकट के समय भी स्थिर बनी रहे। इसी जरूरत ने भारत की ऊर्जा नीति को पिछले वर्षों में अधिक रणनीतिक और दीर्घकालिक बनाया है। विगत वर्षों में भारत ने अब यह समझ लिया है कि ऊर्जा सुरक्षा केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक है।

हालाँकि भारत उन बड़े देशों में शामिल है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जब भी वैश्विक स्तर पर कोई संकट पैदा होता है, उसका असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन हाल के वर्षों में जब ऐसे कई झटके आए, तब भारत ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, वह उल्लेखनीय रहा है। देश ने न केवल तेजी से प्रतिक्रिया दी, बल्कि पूरे संतुलन और स्थिरता के साथ ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखा। इससे पूरी दुनिया में एक संदेश भी गया कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को सिर्फ कागज़ी नीति की तरह नहीं रखा, बल्कि इसे एक लंबे समय की राष्ट्रीय योजना के रूप में अपनाया है।

वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत में ईंधन की कमी नहीं हुई, घरेलू एलपीजी की सप्लाई भी नहीं रुकी और आम लोगों पर इसका असर बहुत सीमित रहा। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई विकसित देश भी ऐसे हालात में प्रभावित हो जाते हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई सालों की तैयारी और निवेश है। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाए, रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाया, पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत किया, बंदरगाहों को आधुनिक बनाया और अलग-अलग देशों से ऊर्जा आयात करके एक ही देश पर निर्भरता कम की। इन सभी कोशिशों की वजह से भारत की ऊर्जा प्रणाली अब पहले से ज्यादा मजबूत और लचीली हो गई है, जिससे वह किसी भी संकट का सामना बेहतर तरीके से कर सकती है।

संकट के समय सरकार ने सिर्फ यह नहीं देखा कि सप्लाई बनी रहे, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा कि आम लोगों पर बोझ कम पड़े। इसके लिए समय पर नियमों में बदलाव किए गए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, दूसरे देशों से वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था की गई और मांग को संतुलित रखने की कोशिश की गई। इससे यह समझ आता है कि ऊर्जा नीति सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ी होती है। भारत की ऊर्जा रणनीति का एक बड़ा हिस्सा विविधीकरण है, यानी अलग-अलग देशों से ऊर्जा लेना ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। आज भारत 40 से ज्यादा देशों से ऊर्जा आयात करता है, जिससे किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर पूरे देश की ऊर्जा व्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ता।

इसी रणनीति के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच ऊर्जा सहयोग भी बहुत मजबूत हुआ है। यह रिश्ता अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति, रणनीतिक भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और ऊर्जा परिवर्तन जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। भारत ने अपनी ऊर्जा कूटनीति को भी मजबूत किया है और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों जैसे पश्चिम एशिया, रूस, अमेरिका, अफ्रीका और मध्य एशिया के साथ संतुलित संबंध बनाए हैं। इसका फायदा यह हुआ कि भारत किसी एक देश या क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहा और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा स्वतंत्रता मिली।

आज भारत केवल अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी सहयोग कर रहा है। भारत ने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को ऊर्जा संकट के समय मदद भी दी है। इससे यह पता चलता है कि भारत केवल अपने विकास पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी ध्यान दे रहा है। कुल मिलाकर, भारत ने यह साबित किया है कि मजबूत ऊर्जा नीति सिर्फ देश की जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण आधार है।

युवा कौशल

प्रमोद भार्गव
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

परिवर्तन का वाहक बनेगा क्वांटम कंप्यूटर

विश्व में क्वांटम तकनीक संचार और गणित में तेजी लाने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य और वित्त के क्षेत्र में बड़े बदलाव की वाहक बनने जा रही है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की दृष्टि से 2023 में ही 'राष्ट्रीय क्वांटम मिशन' की शुरूआत कर दी है। इसका लक्ष्य देश में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसर और क्वांटम पदार्थों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस अभियान के लिए हजारों करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि भारत इस उभरती हुई तकनीक की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे न रह जाए। जिस तरह से इंटरनेट की सुविधा हासिल होने के बाद दुनिया डिजिटल संचार मानचित्र में बदल गई, उसी तरह क्वांटम तकनीक भी भविष्य में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह तकनीक केवल वैज्ञानिकों की ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को तय करने का मापदंड साबित हो सकती है। क्योंकि भारत में 28 से 35 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 65 प्रतिशत और 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 27 फ़ीसदी है।

दुनिया में इस समय दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही हैं। एक समय संगणक के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब कृत्रिम बौद्धिकता ;आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग यानी अति सूक्ष्मता का विज्ञान। भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है। भौतिक शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्युटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही हैं। शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रुचि का विषय हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इस क्वांटम कंप्यूटिंग या मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना अणु या कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता। क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम बौद्धिकता एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने के उपाय हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग या यांत्रिकी एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ अतिसूक्ष्म कण है। इस विषय के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। इनमें परमाणु न्यूक्लियस एवं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन सभी मौलिक कणों का अध्ययन शामिल है। इसमें इनके व्यवहार और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विषय के अध्ययन की नींव 1890 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने डाली थी। हालांकि इस समय तक वैज्ञानिक यह मानकर चल रहे थे कि भौतिकी में जितने नियमों का आविष्कार होना था, लगभग हो चुका है। अब केवल इन नियमों को प्रत्येक जगह क्रियान्वित करना भर शेष है। किंतु कुछ प्रश्न तब भी ऐसे थे, जिनके हल खोजे नहीं जा सके थे। अभी तक काले पिंड के सतत वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) के भिन्न-भिन्न भागों की ऊर्जा के वितरण को परिभाषित नहीं किया जा सका था। इसे समझने के लिए प्लांक ने प्रकाश उत्सर्जन करने वाले द्रव्य कणों की निरंतर चाल के साथ उनमें बिखरी ऊर्जा को भी समझने का विचार दिया। इससे काले पिंड के वर्णक्रम की व्याख्या सुलझ गई। दरअसल इस सोच के परीक्षण में जो निष्कर्ष आएए उनसे ज्ञात हुआ कि ऊर्जा का विकिरण लगातार न होकर टुकड़ों-टुकड़ों में होता है। इन टुकड़ों को विकिरण-कण नाम दिया गया। यह विकिरण भी कणों पर नहीं, बल्कि तरंगों के आधार पर चलता है। यह नियम विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के विपरीत था, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि द्रव्य कणों की गति में विद्यमान ऊर्जा निरंतर गतिशील रहती है। यानी क्वांटम सिद्धांत के तहत अणु, परमाणु और इनके भी मूलभूत कण बेहद लघुतम अवस्था में मौजूद रहते हैं। इस खोज पर 1918 में मैक्स प्लांक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने प्लांक के विकिरण नियम को समझाने के लिए एक सर्वथा नवीन विधि सुझाई। उन्होंने प्रकाश की कल्पना द्रव्यमान रहित कणों के एक गैस पिंड के रूप में ली। इसे फोटॉन गैस के रूप में मान्यता मिली। बाद में इस मान्यता को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी स्वीकृति दी।

विज्ञान ने पहले परमाणु को ही ऐसा सबसे सूक्ष्मतम कण बतलाया था, जिसने विश्व का निर्माण किया है। फिर आगे की खोज से ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है। यानी उसे और अत्यंत सूक्ष्म कणों में बांटा जा सकता है। फलतः ये सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के लघुतम रूपों में सामने आए। कालांतर में कण मसलन क्वांटम भौतिकी और विकसित रूपों में सामने आई। तब पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और विभाजित किया जा सकता है। अंततः इसे क्वार्क व लैपटॉन जैसे सूक्ष्म कणों में विभाजित कर भी लिया गया। इस तरह से कण भौतिकी में एक प्रामाणिक प्रतिदर्श सामने आया,जिसमें क्वार्क व लैप्टॉन के बारह सूक्ष्मतम कणों के प्रकार दर्ज हैं। इन्हें जरूर अब तक अविभाज्य माना गया है। अब इन्हें ही मूलकण माना जा रहा है। आधुनिक विज्ञान में यह धारणा बन रही है कि पदार्थ से संबंधित अत्यंत कम द्रव्यमान वालेए इन्हीं मूल कणों से सृष्टि के जड़ एवं चेतन स्वरूप अस्तित्व में आए हैं।

कण यांत्रिकी को कल के कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है।यह परमाणु और उप परमाणु के स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की व्याख्या करती है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट; अंशद्ध पर काम करते हैं वहीं क्वांटम कंप्यूटर में प्राथमिक इकाई क्यूबिट यानी कणांश होती है। पारंपरिक कंप्यूटर में प्रत्येक बिट का मूलाधार या मूल्य शून्य (0) और एक (1) होता है। कंप्यूटर इसी शून्य और एक की भाषा में ही कुंजी पटल (की-बोर्ड) से दिए निर्देश को ग्रहण करके समझता है और परिणाम को अंजाम देता है। वहीं क्वांटम की विलक्षणता यह होगी कि वह एक साथ ही शून्य और एक दोनों को ग्रहण कर लेगा। यह क्षमता क्यूबिट की वजह से विकसित होगी। परिणामस्वरूप यह दो क्यूबिट में एक साथ चार मूल्य या परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। एक साथ चार परिणाम स्क्रीन पर प्रकट होने की इस अद्वितीय क्षमता के कारण इसकी गति पारंपरिक कंप्यूटर से कहीं बहुत ज्यादा होगी। इस कारण यह पारंपरिक कंप्युटरों में जो कूट.रचना या गूढ लेखन कर दिया जाता है, उससे कहीं अधिक मात्रा में यह कंप्यूटर डाटा ग्रहण व सुरक्षित रखने में समर्थ होगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से आंकड़ों और सूचनाओं को कम से कम समय में प्रसारित किया जा सकेगा। एआईएजीपीटी चेट और चैटबॉट जैसी तकनीक इसकी सहायता से और तेजी से गतिशील रहेंगी। लेकिन विलो चिप निर्माण कर लिए जाने की घोषणा ने सुपर कंप्यूटर के निर्माताओं को फिलहाल सकते में डाल दिया है। क्योंकि विलो चिप की क्षमताएं ब्रह्मांड व्यास की तरह शक्तिशाली और असीमित बताई गई हैं।

क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता को देखते हुए इसके विकास में भारतसमेत अनेक देश लगे हैं। यही वजह है कि आविष्कार से पहले इसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर लेने वाले देश इसके अनुसंधान पर बढ़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं। चीन ने 15 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है, चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा अलग से इस पर काम कर रही है। यूरोपीय यूनियन इस क्षेत्र में करीब 8 अरब डॉलर खर्च कर रही है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम सूचना-विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था का गठन तो पहले ही कर लिया था, लेकिन केवल क्वांटम तकनीक पर नवीन शोध और आविष्कार के लिए 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाले इस अभियान पर इस 6003.65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत इतनी बड़ी धनराशि पहली बार खर्च कर रहा है।

फिलहाल ऐसा भी माना जा रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी का क्षेत्र जितना महत्वपूर्ण है,उस तुलना में इस क्षेत्र में कुशल युवाओं की संख्या बहुत कम है। एक अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में कुछ हजार से भी कम लोग क्वांटम अभियांत्रिकी या भौतिकी में शोधरत हैं। अनेक कंपनियां कल्पनाशील एवं योग्य लोगों की तलाश में हैं। हैरानी इस पर भी है कि इस क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाएं होने के बावजूद इस जटिल विषय की ओर युवा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कुशाग्र बुद्धि वाले जो विद्यार्थी कल्पनाशील विचार रखते हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाकर इस मेधा शक्ति को कंपनियों के पारंपरिक कार्यों में खपाया जा रहा है या सरकारी नौकरियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अतएव भारत के इंजीनियरिंग तकनीक से शिक्षित युवा इस तकनीक में कौशल दक्षता दिखा सकते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

मुकेश नेमा
लेखक मध्यप्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

कैसे करते हैं बुढ़ापे में दूसरी तीसरी या चौथी शादी का फैसला?

आज मैं उन बहादुरों की चर्चा करना चाहूँगा जिन्होंने भरे बुढ़ापे में दूसरी,तीसरी या चौथी शादी की हुई है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। इमरान खान तो हमारे सलाम के लायक है ही वे पहले ही तीसरी कर चुके, हमारे आमिर खान अब जाकर इस मामले मे इमरान की बराबरी कर सके है। आमिर ने हम करोड़ों हिंदुस्तानियों का मान बढ़ाया है। वे और उन जैसे दूसरे धीर वीर लोग वो कर गये है जो मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग भरपूर मन होने के वावजूद कायरता वश कर नही सके है।

मैं यह सोच कर भी ऐसे बहादुर लोगो से जलता हूं कि भाई उस लुप्त होती प्रजाति से है जो अपनी बीबी से डरता नहीं है और उसे क़ाबू मे रखने का गुर जानता है। दूसरी शादी करने का फ़ैसला यह नतीजा निकालने के लिये काफी है कि यह भाई अब तक अपनी ज़िंदगी मे मनमानी करता आया है और एक शादी करने के बावजूद खुदमुख्तार है। आज के कठिन समय में, जब लोगों के लिए एक को संभालना मुश्किल है ऐसे मे दूसरी शेरवानी सिलवा लेने वाले व्यक्ति की मैनेजमैंट काबिलियत से जलने के बावजूद मैं सदा से यह जानने के लिये बैचैन रहा हूँ कि वो ऐसा कर कैसे कर पाते हैं। चूँकि ये वीर पुरूष प्रायः अपने इस पुरूषार्थ पर प्रकाश डालने मे संकोच करते है इसलिये मुझे आज खुद इनको प्रकाशित करने की ज़िम्मेदारी उठाना पड़ रही है।

पहले पहली जिज्ञासा का शमन किया जाये कि ये ऐसा कर कैसे पाते हैं? तो मेरा ख्याल तो यह है कि हर वह मालदार बूढा जिसका भारी पर्स उससे संभल ना पा रहा हो इस भारी भरकम जिम्मेदारी को सँभालने के लिये किसी सुंदरी को ही चुनना चाहता है। और जब भी दूसरी के आने का सुयोग हो जाता है वह बहुत जल्दी कूद कर इस नतीजे पर पहुँच जाता है। परमात्मा ने इस दर्शनीया को जन्म ही इसलिये दिया है कि वो उस पर भरोसा कर चिंतामुक्त हो सके। वैसे बूढ़े पके पकाये धनिकों की संगत मे आते ही कतिपय दूरदर्शी बालाओं के मन मे भी कुछ ऐसी ही भरोसा दिलाने टाईप की तरंगे उठती है। वैसे भी उसकी इतनी सारी योग्यताओ के कारण किसी दूरदर्शी गुणवान और परोपकारी सुकन्या का उसकी सहायता करने को सहर्ष प्रस्तुत हो उठना अत्यंत स्वाभाविक ही है, यह परस्पर सहयोग का सिद्धांत है। बूढ़ा आदमी और उसकी दूसरी पत्नी बनने के लिये सहमत कन्या दोनों को ही अच्छे दिनो की उम्मीद होती है, ओर जैसा कि ऐसे मामलों मे होता ही है बुजुर्गवार ज्यादा दिनो तक अच्छे दिन बर्दाश्त नही कर पाते, और यथाशीघ्र स्वर्गवासी होकर उस सुंदरी के अच्छे दिनों की ग्यारंटी हो जाते हैं। यदि वे इस नेक काम को करने मे विलम्ब करते है तो उनकी दूसरी पत्नी उन्हे ज़हर या घर की बॉलकनी से धक्का दे देने जैसै निरापद उपायों पर विचार करने के लिये भी सहर्ष प्रस्तुत बनी रहती है।

मेरे भोले-भाले मित्रों के मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न होगा कि चलिए मान लिया कि बब्बा की पहली भली बीबी ने मन मार लिया होगा पर जवान औलादों को तो क़ायदे से ऐसे नाजुक मौक़ों पर बाप की कॉलर पकड़ ही लेना चाहिये? वे ऐसा क्यों नहीं करते? जाहिर है वे ऐसा नहीं करते और इसलिये नहीं करते क्योंकि वे भी समझदार बाप की अति समझदार औलादे हैं। बाप का पर्स एक बार फिर उसकी रक्षा करता है। औलादें वसीयत से बेदख़ल नहीं होना चाहती और अपनी नयी माँ का आदर करते हुये उसके साथ मिलकर अपने पुराने बाप के सिधार जाने की प्रतीक्षा करने लगती हैं।

किसी भी रईस बूढ़े आदमी के दुबारा ब्याह करने के फ़ैसले भर से उसकी भावी पत्नी के साथ उसका बेरोज़गार युवा प्रेमी भी प्रसन्न हो जाता है। इस साहसिक कृत्य से बुढ़ऊ की सामाजिक स्वीकार्यता और प्रतिष्ठा रातों रात बढ़ जाती है। आसपास रहने वाले वे सभी जो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे अनायास नमस्कार करने लगते हैं। पड़ोसी भी अपने अच्छे दिनों की उम्मीद में आशान्वित हो जाते हैं, बूढ़ा आदमी रातों-रात एक खूसट और चिड़चिड़े आदमी से प्रसन्नचित्त अधेड़ मे बदल जाता है। पतझड़ में आ धमका यह आकस्मिक बंसत उसे अस्त व्यस्त कर देता है। उसे और कुछ सूझता नहीं और उसके मुनीम मैनेजर इसे चार पैसै बना लेने का सुअवसर मान कर इसका लाभ उठाते है।

कुल मिलाकर मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि किसी भी अमीर बुज़ुर्गवार का दुबारा ब्याह करने का क्रांतिकारी फ़ैसला उसकी दूसरी पत्नी के आर्थिक और उसके प्रेमी और पड़ोसियों के हमारे भी अच्छे दिन आयेंगे वाले दृष्टिकोण से अत्यंत लोक कल्याणकारी क़दम है। और मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे सारे अड़ोसी पड़ोसी बुज़ुर्ग भी इसी तरह का साहसिक क़दम उठाने के लिये प्रेरित हों, किसी तीखे नैन नख्श वाली अनाथ दरिद्र और महत्वाकांक्षी सुंदरी का उद्धार करें और उनके पड़ोसी होने के कारण भर से मैं अपने आपको संभावित लाभान्वितों मे गिन कर प्रसन्न हो सकूँ।

विचार

डॉ. लोकेन्द्र सिंह कोट

लेखक स्तंभकार हैं।

धूल चश्में पर है, दुनिया तो पाक-साफ है

'समान नागरिक संहिता' की अवधारणा स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के संवैधानिक ढांचे का अंग रही है। इसे राज्य के नीति के निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन दशकों से बहस और विवाद का विषय रहा है। समान नागरिक संहिता के इर्द-गिर्द होने वाली चर्चा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और समान नागरिक विधिक एवं भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन जैसे संवेदनशील मुद्दों का स्पर्श करती है।

कभी-कभी जीवन के बड़े सत्य पुस्तकालयों में नहीं, सड़कों पर मिलते हैं। वे शोध-पत्रों में नहीं, लोगों की आँखों में लिखे होते हैं। हम उन्हें पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास पूर्वाग्रहों का चश्मा होता है। कुछ समय पहले हमने एक छोटा-सा सामाजिक प्रयोग किया। आजकल की भाषा में इसे 'प्रैंक' कहा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए यह मनोरंजन नहीं था। यह मनुष्य और समाज को समझने का एक प्रयास था।

हमने साधारण और मैले कपड़े पहने। चेहरा थका हुआ और असहाय बनाया। शहर की गलियों, बाजारों और चौक-चौराहों पर घूमे। कभी भोजन माँगा, कभी चाय के लिए कुछ पैसे। कहीं दुकानदारों के सामने खड़े हुए, कहीं राहगीरों के सामने हाथ फैलाया। हम यह जानना चाहते थे कि जिन लोगों के बारे में हमें प्रतिदिन बताया जाता है कि वे स्वार्थी, कठोर और संवेदनहीन हो चुके हैं, वे वास्तव में कैसे हैं। दिनभर का अनुभव हमारे लिए आश्चर्य से भरा था। किसी ने भोजन कराया। किसी ने चाय पिलाई। किसी ने बिना पूछे पैसे थमा दिए। किसी ने हालचाल पूछा। किसी ने कहा, 'भाई, भगवान भला करेगा।' हाँ, कुछ लोगों ने डाँटा भी। कुछ ने शक की दृष्टि से देखा। कुछ ने उपेक्षा की। लेकिन जब हमने पूरे दिन का लेखा-जोखा तैयार किया तो पाया कि लगभग अस्सी प्रतिशत लोगों ने किसी न किसी रूप में सहायता की थी। उस रात एक प्रश्न मन में देर तक जागता रहा– यदि दुनिया इतनी बुरी है, तो ये अच्छे लोग कहाँ से आए?

डर बेचने वाली दुनिया

हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ भय सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। सुबह अखबार खोलिए– हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सड़क दुर्घटना। मोबाइल खोलिए– घृणा, विवाद, अफवाहें, आरोप। टीवी चलाइए– चिल्लाहट, आरोप-प्रत्यारोप और उत्तेजना।

धीरे-धीरे हमारे भीतर यह विश्वास बैठने लगता है कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है और मनुष्य की अच्छाई समाप्त हो गई है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि सचमुच ऐसा होता तो यह सभ्यता अब तक चल कैसे रही होती?

हर सुबह करोड़ों लोग समय पर काम पर जाते हैं। लाखों शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। किसान खेतों में अन्न उगाते हैं। डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों का उपचार करते हैं। माताएँ बच्चों को भोजन कराती हैं। पड़ोसी एक-दूसरे की सहायता करते हैं। इनमें से कोई भी समाचार नहीं बनता। समाचार वही बनता है जो असामान्य हो। और दुर्भाग्य से बुराई हमेशा असामान्य होने के कारण आकर्षित करती है।

मनोविज्ञान का एक रहस्य : हम बुराई जल्दी देखते हैं

मनोवैज्ञानिक इसे 'नेगेटिविटी बायस' कहते हैं। मानव मस्तिष्क लाखों वर्षों के विकासक्रम में इस प्रकार बना है कि वह खतरे को जल्दी पहचान सके। जंगल में रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए यह आवश्यक था। जो व्यक्ति खतरे को जल्दी पहचानता था, उसके जीवित रहने की संभावना अधिक होती थी। इसी कारण आज भी हमारा मन बुरी खबरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। एक सड़क पर सौ लोग मुस्कुराकर निकल जाएँ तो हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति दुर्व्यवहार कर दे तो वही स्मृति में रह जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर ने लिखा है– 'खराब, अच्छे से ज्यादा शक्तिशाली है' अर्थात बुराई का प्रभाव अच्छाई की तुलना में अधिक तीव्र होता है। यही कारण है कि हम संसार की अच्छाई को कम और बुराई को अधिक देखने लगते हैं।

एक रोटी और पूरी मानवता

हमारे प्रयोग में एक घटना विशेष रूप से स्मरणीय है। एक बुजुर्ग महिला मंदिर के बाहर मिलीं। हमने उनसे कुछ सहायता माँगी। उन्होंने पर्स नहीं खोला। वे घर के भीतर गईं और दो रोटियाँ तथा थोड़ी सब्जी लेकर आईं। उन्होंने कहा– 'बेटा, पैसे न हों तो भी कोई बात नहीं, भूखे मत रहना।' उस क्षण हमें लगा कि हम किसी साधारण महिला से नहीं, भारतीय संस्कृति की हजारों वर्षों पुरानी करुणा से मिल रहे हैं।

तुलसीदास ने लिखा है– 'परहित सरिस धरम नहि भाई।' दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं। संभवतः हमारी सभ्यता का वास्तविक आधार यही है। उपनिषदों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सदियों पहले घोषणा की थी– 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यह पृथ्वी एक परिवार है।

जब कोई अजनबी किसी अजनबी की सहायता करता है तो वह इसी भाव का विस्तार है। रोचक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अब इसी निष्कर्ष तक पहुँच रहा है। हार्वर्ड

विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुए अनेक अध्ययनों से पता चला है कि अधिकांश मनुष्य परिस्थितियाँ मिलने पर सहयोग करना पसंद करते हैं।

समाजशास्त्री इसे सामाजिक विश्वास कहते हैं। यदि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता तो समाज का निर्माण ही संभव नहीं था। कोई बाजार नहीं चलता। कोई विद्यालय नहीं चलता। कोई अस्पताल नहीं चलता। सभ्यता स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सहयोग प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक व्यापक है।

एक रिक्शेवाले का दर्शन

उस दिन एक रिक्शा चालक मिला। उसकी कमीज पुरानी थी। चेहरे पर श्रम की रेखाएँ थीं। हमने उससे भोजन के लिए कुछ सहायता माँगी। उसने जेब टटोली। कुछ सिक्के और एक बीस रुपये का नोट निकला। उसने नोट हमारी ओर बढ़ाते हुए कहा– 'मेरे पास इतना ही है, लेकिन तुम रख लो।' हमने सोचा– जिसके पास स्वयं कम है, वही सबसे अधिक देने को तैयार क्यों होता है? शायद इसलिए कि अभाव मनुष्य को पीड़ा का अर्थ सिखाता है। जिसने भूख देखी होती है, वही दूसरे की भूख समझता है।

करुणा का जैविक विज्ञान

यह केवल दर्शन नहीं, विज्ञान भी है। शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं। अर्थात सहायता करना केवल सामाजिक व्यवहार नहीं, जैविक आनंद भी है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को भोजन कराता है तो संतोष केवल पाने वाले को नहीं, देने वाले को भी मिलता है। भारतीय परम्परा ने इसे 'पुण्य' कहा। विज्ञान इसे 'हेल्पर हाई' कहता है। नाम अलग-अलग हैं, अनुभव एक ही है।

समाचारों के बाहर की दुनिया

हमने बाद में कई और छोटे-छोटे सामाजिक प्रयोग किए। कहीं रास्ता पूछने का नाटक किया। कहीं सहायता माँगी। कहीं किसी अनजान व्यक्ति से मदद चाही। परिणाम लगभग एक जैसे थे। लोगों में अच्छाई अपेक्षा से कहीं अधिक थी। तबसमझ आया कि हम संसार को प्रत्यक्ष अनुभव से कम और माध्यमों के माध्यम से अधिक जानते हैं। और माध्यम अक्सर वही दिखाते हैं जो बेचता है। भय बिकता है। क्रोध बिकता है। विवाद बिकता है। करुणा नहीं बिकती। इसलिए वह दिखाई कम देती है।

संतों की दृष्टि

कबीर कहते हैं– 'बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय॥' समस्या संसार में कम और दृष्टि में अधिक होती है। महात्मा गांधी ने कहा था– 'यदि दुनिया में केवल बुराई होती, तो मानवता बहुत पहले समाप्त हो चुकी होती।' बुद्ध ने मनुष्य को 'करुणा का पात्र' कहा। गुरु नानक ने 'सेवा' को ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया। सभी संत मानो एक ही बात कह रहे थे– मनुष्य के भीतर प्रकाश अभी भी जीवित है।

अच्छाई कभी सुर्खियाँ नहीं बनती- कल्पना कीजिए– आज पूरे भारत में करोड़ों लोगों ने किसी की सहायता की होगी। किसी ने रास्ता बताया होगा। किसी ने किसी को अस्पताल पहुँचाया होगा। किसी ने भूखे को भोजन कराया होगा। किसी ने रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना दी होगी। लेकिन इनमें से अधिकांश घटनाएँ कहीं दर्ज नहीं होंगी। वे न अखबार में छपेंगी, न टीवी पर दिखेंगी। वे केवल कुछ हृदयों में स्मृति बनकर रह जाएँगी। और शायद यही अच्छाई का स्वभाव है। वह प्रदर्शन नहीं करती। वह बस अपना काम करती रहती है।

मनुष्य पर विश्वास बचा रहना चाहिए- उस दिन हम भिखारी बनकर निकले थे, लेकिन लौटे तो मनुष्य की संपन्नता देखकर। हमें धन नहीं मिला था। हमें विश्वास मिला था। विश्वास कि दुनिया अभी भी करुणा से भरी है। विश्वास कि अधिकांश लोग अच्छे हैं। विश्वास कि मानवता अभी समाप्त नहीं हुई। हाँ, संसार में बुराई है। अन्याय है। हिंसा है। लेकिन वे पूरी कहानी नहीं हैं। पूरी कहानी उन लाखों लोगों की भी है जो प्रतिदिन बिना किसी पुरस्कार, प्रशंसा या पहचान के दूसरों की सहायता करते हैं।

इसलिए अब जब कोई कहता है कि दुनिया बहुत खराब हो गई है, तो मुझे उस दिन की सड़कें याद आती हैं, वे चाय पिलाने वाले लोग याद आते हैं, वह रोटी देने वाली माँ याद आती है, वह रिक्शेवाला याद आता है। और तब मन कहता है– धूल चश्में पर है, दुनिया तो पाक-साफ है। वह आज भी प्रेम, करुणा और संवेदना के अनगिनत दीपकों से प्रकाशित है। बस हमें समाचारों की चमक से आँखें हटाकर उन दीपकों को देखना सीखना होगा।

मुद्दा

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।

आराम की दौड़ में सुरक्षा से समझौता क्यों?

भीषण गर्मी के इस दौर में एयर कंडीशनर अब केवल विलासिता का साधन नहीं रह गया है। पहले जहाँ एसी केवल बड़े घरों, कार्यालयों या होटलों तक सीमित था, वहीं आज मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में भी यह आम जरूरत बन चुका है। लगातार बढ़ते तापमान और बदलती जीवनशैली ने एसी को रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना दिया है। लेकिन सुविधा का यह साधन तभी तक उपयोगी है, जब तक उसका उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाए। जैसे-जैसे एसी का उपयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे उससे जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत लापरवाही का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी खामियाँ, घटिया गुणवत्ता वाले उपकरण, अपर्याप्त रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-119 स्थित एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में हाल ही में एयर कंडीशनर (एसी) में हुए विस्फोट से लगी आग ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आधुनिक सुविधाएँ यदि सावधानी के साथ न अपनाई जाएँ तो वही जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को कई घंटे लग गए। इससे पहले भी देश के विभिन्न शहरों में एसी फटने या उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की अनेक घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। इन हादसों ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल तकनीक पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है।

भीषण गर्मी के इस दौर में एयर कंडीशनर अब केवल विलासिता का साधन नहीं रह गया है। पहले जहाँ एसी केवल बड़े घरों, कार्यालयों या होटलों तक सीमित था, वहीं आज मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में भी यह आम जरूरत बन चुका है। लगातार बढ़ते तापमान और बदलती जीवनशैली ने एसी को रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना दिया है। लेकिन सुविधा का यह साधन तभी तक उपयोगी है, जब तक उसका उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाए। जैसे-जैसे एसी का उपयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे उससे जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत लापरवाही का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी खामियाँ, घटिया गुणवत्ता वाले उपकरण, अपर्याप्त रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

एसी में आग लगने या विस्फोट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है मशीन का लगातार कई घंटों तक बिना रुके चलना। जब कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उसका तापमान तेजी से बढ़ जाता है। यदि समय पर मशीन को विश्राम न मिले या उसमें पहले से कोई तकनीकी खराबी हो तो वह गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त गैस का रिसाव, विद्युत तारों का ढीला या खराब होना, ओवरलोडिंग, निम्न गुणवत्ता के पुर्जों का उपयोग तथा गलत तरीके से इंस्टॉलेशन भी आग लगने की आशंका बढ़ा देते हैं। कई बार लोग सस्ते और बिना प्रमाणित उपकरण खरीद लेते हैं, जो थोड़े समय बाद ही जोखिम पैदा करने लगते हैं।

समस्या का एक बड़ा कारण नियमित रखरखाव का अभाव भी है। अधिकांश लोग एसी खरीदने के बाद वर्षों तक उसकी सर्विस नहीं कराते। धूल और गंदगी के कारण फिल्टर जाम हो जाते हैं, कंडेंसर पर दबाव बढ़ जाता है और मशीन अधिक बिजली खींचने लगती है। धीरे-धीरे यही स्थिति किसी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। यदि समय-समय पर प्रशिक्षित तकनीशियन से एसी की जांच कराई जाए, गैस का स्तर देखा जाए और बिजली की वायरिंग की स्थिति पर ध्यान दिया जाए, तो अधिकांश हादसों को रोका जा सकता है।

बढ़ती दुर्घटनाओं के पीछे एक और चिंता का विषय बाजार में उपलब्ध निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कई कंपनियाँ कम कीमत पर उपकरण बेचने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर लेती हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता भी कम कीमत के लालच में बिना प्रमाणित उत्पाद खरीद लेते हैं। ऐसे उपकरणों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता और उनमें प्रयुक्त पुर्जे भी टिकाऊ नहीं होते। परिणामस्वरूप थोड़ी-सी तकनीकी खराबी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। इसलिए उपभोक्ताओं को हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद कंपनियों के उत्पाद ही खरीदने चाहिए।

यह समस्या केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी विकास और भवन निर्माण व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। आज महानगरों में ऊँची-ऊँची इमारतें तेजी से बन रही हैं, लेकिन उनमें अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन हमेशा संतोषजनक नहीं होता। कई इमारतों में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और आपातकालीन निकासी मार्ग केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। नियमित मॉक ड्रिल नहीं होती और निवासी भी आपदा की स्थिति में क्या करना चाहिए, इससे अनजान रहते हैं। परिणामस्वरूप छोटी-सी आग भी भयावह रूप धारण कर लेती है।

दमकल विभाग की चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। देश के अनेक शहरों में संसाधनों और आधुनिक उपकरणों का अभाव है। ऊँची इमारतों तक पहुँचने वाली हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ और उच्च क्षमता वाले अग्निशमन उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। कई बार संकरी सड़कें, अवैध पार्किंग और अव्यवस्थित यातायात भी दमकल वाहनों के समय पर पहुँचने में बाधा बन जाते हैं। ऐसे में आग पर नियंत्रण पाने में देरी होती है और नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। यह स्थिति बताती है कि केवल नागरिकों की सतर्कता ही नहीं, बल्कि सरकारी तैयारियों को भी अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन भी इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। हर वर्ष तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे एसी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। बिजली की मांग बढ़ने से विद्युत व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कई क्षेत्रों में पुरानी वायरिंग और ओवरलोड ट्रांसफार्मर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा देते हैं। इसलिए ऊर्जा अवसंरचना को भी समय के अनुरूप आधुनिक बनाना आवश्यक है, ताकि बढ़ती जरूरतों को सुरक्षित ढंग से पूरा किया जा सके।

इसका समाधान केवल सरकार या कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एसी को लगातार कई घंटों तक बिना आवश्यकता के न चलाना, समय-समय पर उसकी सर्विस कराना, सही क्षमता वाले बिजली के तार और एमसीबी का उपयोग करना, एक्सटेंशन बोर्ड से भारी उपकरण न चलाना तथा घर में अग्निशामक यंत्र रखना जैसी छोटी-छोटी सावधानियाँ बड़े हादसों को रोक सकती हैं। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सुरक्षित तरीके से बाहर कैसे निकला जाए और तुरंत दमकल विभाग को सूचना कैसे दी जाए।

वास्तव में आधुनिक तकनीक का उद्देश्य जीवन को सरल और आरामदायक बनाना है, न कि उसे संकट में डालना। इसलिए सुविधा और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नोएडा जैसी घटनाएँ केवल समाचार नहीं हैं, बल्कि चेतावनी हैं कि यदि हम अभी भी नहीं चेते तो भविष्य में ऐसे हादसे और बढ़ सकते हैं। सरकार को सुरक्षा मानकों का कठोर पालन सुनिश्चित करना होगा, भवन निर्माताओं को अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने होंगे और नागरिकों को जिम्मेदार उपभोक्ता बनना होगा। जब तकनीक के साथ सतर्कता, गुणवत्ता के साथ जिम्मेदारी और सुविधा के साथ सुरक्षा भी जुड़ जाएगी, तभी आधुनिक जीवन वास्तव में सुरक्षित, सुखद और विश्वासपूर्ण बन सकेगा।

पर्यावरण

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

ओक वृक्षों पर संकट वैश्विक पारिस्थितिक चेतावनी

जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट की चर्चा जब भी होती है, तब आमतौर पर ग्लेशियरों के पिघलने, जंगलों की आग, सूखे और बाढ़ जैसे विषय प्रमुखता से सामने आते हैं। किंतु प्रकृति में कुछ संकट ऐसे भी होते हैं जो अचानक नहीं आते, बल्कि वर्षों तक धीरे-धीरे विकसित होते हैं और जब उनके परिणाम स्पष्ट दिखाई देते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। ओक (बलूत) वृक्षों के सामने खड़ा संकट ऐसी ही एक धीमी लेकिन गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। हाल ही में ब्रिटेन में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट ने इस संकट को नए सिरे से वैश्विक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति अलग-अलग प्रकार के दबावों का सामना कर रही है। भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भी ओक वनों का क्षरण पर्यावरणविदों की चिंता का सबब बना हुआ है।

क्या है ओक वृक्ष?

ओक वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्वेरकस (Quercus) है। यह फैगेसी (Fagaceae) कुल का सदस्य है और विश्वभर में इसकी लगभग 500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों में इसका व्यापक फैलाव है। भारत में मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में इसकी अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें बांज (Quercus leucotrichophora), तिलौंज, खरसू और मोरू प्रमुख हैं।

ओक वृक्ष अत्यंत दीर्घायु होते हैं। कुछ वृक्ष 300 से 500 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जबकि कई प्राचीन ओक वृक्षों की आयु इससे भी अधिक दर्ज की गई है। अपनी विशाल छत्राकार संरचना, गहरी जड़ों और दीर्घ जीवन के कारण इन्हें अनेक पारिस्थितिक तंत्रों की आधारशिला माना जाता है।

पारिस्थितिकी का प्रहरी

ओक वृक्षों का महत्व केवल उनकी विशालता या सुंदरता तक सीमित नहीं है। इन्हें जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। ब्रिटेन में किए गए अध्ययनों के अनुसार एक ओक वृक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2,300 से अधिक जीव प्रजातियों को आश्रय देता है। इनमें पक्षी, कीट, कवक, काई, स्तनधारी और सूक्ष्मजीव शामिल हैं।

भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भी ओक वन पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें 'जल संरक्षक वृक्ष' कहा जाता है क्योंकि इनकी गहरी जड़ें वर्षा जल को भूमि में संरक्षित करती हैं और झरनों, नालों तथा नदियों के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि जिन क्षेत्रों में ओक वन सुरक्षित हैं, वहां जलस्रोत अपेक्षाकृत अधिक स्थायी बने रहते हैं।

इसके अलावा ओक वृक्ष कार्बन अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक परिपक्व ओक वृक्ष अपने जीवनकाल में बड़ी मात्रा में कार्बन संग्रहीत कर सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है।

एशियाई देशों में ओक वनों की स्थिति

भारत में ओक मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किंतु पिछले कुछ दशकों में इन वनों का क्षेत्रफल और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुई हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार ओक वनों के क्षरण के पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि और वर्षा चक्र में बदलाव से इनके प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में ओक वनों की जगह चीड़ (पाइन) के जंगल फैल रहे हैं। चीड़ अपेक्षाकृत कम जैव विविधता का समर्थन करती है और जंगल की आग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।

इसके अतिरिक्त ईंधन, चारे और लकड़ी के लिए अत्यधिक दोहन, अनियंत्रित चराई, सड़क निर्माण और शहरी विस्तार भी ओक वनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। कई अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया है कि पुराने वृक्ष तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन नए पौधों का प्राकृतिक पुनर्जनन लगातार घट रहा है। यह स्थिति भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है।

नेपाल, भूटान और चीन के पर्वतीय क्षेत्रों में भी ओक वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दर्ज किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान बढ़ने के कारण कई ओक प्रजातियाँ ऊंचाई की ओर खिसक रही हैं, जिससे उनकी पारिस्थितिक सीमाएं बदल रही हैं।

ब्रिटेन में ओक वृक्ष केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा हैं। इस देश में लगभग 17 करोड़ ओक वृक्ष मौजूद हैं और लगभग 50 हजार प्राचीन ओक वृक्षों का रिकॉर्ड है।

शोध रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के ओक वृक्ष कई खतरों का एक साथ सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, सूखा, रोग, कीट आक्रमण, हिरणों द्वारा अत्यधिक चराई, ग्रे गिलहरियों द्वारा छाल को नुकसान पहुंचाना तथा विकास परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों का विनाश शामिल है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्या किसी एक कारण की नहीं है, बल्कि अनेक दबावों के संयुक्त प्रभाव की है। यही कारण है कि इसे 'धीमी गति से बढ़ती पारिस्थितिक आपदा' कहा जा रहा है।

ब्रिटेन में वर्तमान समय का सबसे गंभीर संकट एक्यूट ओक डिक्लाइन नामक बीमारी है। यह बैक्टीरिया और एक विशेष बीटल के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। सूखा और पर्यावरणीय तनाव इस बीमारी को और घातक बना देते हैं। इस रोग से प्रभावित वृक्षों की छाल पर दरारें पड़ जाती हैं और उनसे गहरे रंग का तरल पदार्थ रिसने लगता है। चिंताजनक तथ्य यह है कि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले वृक्ष केवल तीन से छह वर्षों के भीतर नष्ट हो सकते हैं। वर्ष 2023 तक इसके लगभग 394 प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी थी।

इसके अलावा ओक पाउडरी मिल्ड्यू, ओक प्रोसेशनरी मॉथ, नॉपर गॉल वास्प तथा ओक लेस बग जैसे कीट और रोग भी वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैश्विक व्यापार और जलवायु परिवर्तन के कारण इन खतरों का प्रसार तेज हो रहा है।

संकट केवल वृक्षों का नहीं

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओक वृक्षों की संख्या में गिरावट जारी रही तो इसका प्रभाव केवल वनों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे हजारों जीव प्रजातियों का आवास प्रभावित होगा, कार्बन भंडारण क्षमता घटेगी, जल चक्र पर असर पड़ेगा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। ब्रिटेन में ओक वृक्ष लगभग 31 मिलियन टन कार्बन संग्रहीत करते हैं। ऐसे में इनका क्षरण जलवायु संकट को और गंभीर बना सकता है।

संरक्षण की दिशा में क्या किया जाए?

ओक वृक्षों का संरक्षण केवल वन विभागों या वैज्ञानिकों का दायित्व नहीं है। इसके लिए बहुस्तरीय प्रयासों की आवश्यकता है। रोगों और कीटों की निगरानी, वैज्ञानिक शोध, प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा, नियंत्रित चराई और विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय संवेदनशीलता आवश्यक है।

भारत में सामुदायिक वन प्रबंधन और पारंपरिक संरक्षण प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ओक वनों के संरक्षण के कई उदाहरण सामने आए हैं। उनमें हिमालयी क्षेत्रों में पवित्र वन जैसी परंपराएँ ओक संरक्षण का एक उदाहरण हो सकती हैं।

एक वैश्विक चेतावनी

ओक का संकट केवल एक देश की समस्या नहीं है। यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास और मानवीय दबाव मिलकर किस प्रकार प्रकृति की सबसे मजबूत दिखने वाली प्रजातियों को भी कमजोर कर सकते हैं।

यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो ओक वृक्षों के साथ-साथ उनसे जुड़े हजारों जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए यह केवल एक वृक्ष की कथा नहीं, बल्कि पृथ्वी की पारिस्थितिक सुरक्षा और मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखकर स्तंभकार हैं।

बनती, बिगड़ती और टूटती अवधारणाएं

वैसे तो सत्य हमेशा शाश्वत होता है लेकिन देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप इसमें काफी हद तक परिवर्तन भी आ जाता है। एक समय का सच अलग-अलग कालखंड में अलग-अलग स्वरूप में भी माना जा सकता है। इसके चलते न केवल महापुरुष अपितु अलग-अलग तरह की विचारधारा और देवत्व को प्राप्त विभूतियों के प्रति भी आम धारणा पर सवाल उठ जाया करते हैं। कोई किसी भी क्षेत्र में कितना भी महान क्यों न हो, उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर नाना प्रकार के सवाल गहरा जाते हैं। इसके चलते वर्तमान दौर में लगभग हर कोई संदेह के दायरे में आता दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे में आम आदमी 'किंतु परंतु' के चक्र में उलझ कर रह जाता है।

जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति, विचारधारा और आम जनधारणा के बारे में भी सिक्के को उलटने-पलटने की मनोवृति के चलते अलग-अलग दृष्टिकोण से आकलन किया जाने लगा है। दरअसल इसका कोई सर्वमान्य हल कहीं से कहीं तक दिखाई भी नहीं देता। वर्तमान दौर में आदमी की तर्कशक्ति तो प्रबल हुई ही है लेकिन कुतर्क शक्ति भी इसी अनुपात में बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि हर किसी अवधारणा पर लगातार सवाल उठाए जाने लगे हैं। इसके चलते अनेक अवसरों पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। इस समय बहुत तेजी के साथ अलग-अलग विचारधारा का ध्रुवीकरण होता दिखाई देता है।

हालांकि आजकल आदमी का नजरिया काफी हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आत्मसात करने का हो गया है। जिसके चलते सोचने समझने के पैमाने भी लगातार बदलते जा रहे हैं। लेकिन हम हर किसी बात को केवल और केवल वैज्ञानिक नजरिए से ही नहीं देख सकते। कई बार अंतरंग में स्थापित अवधारणा, जिसका कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक लंबा इतिहास रहा है, उससे इतर किसी अन्य अवधारणा को आत्मसात करना कतई संभव नहीं होता। आदमी का आचार विचार और व्यवहार पारिवारिक संस्कारों के आधार पर निर्धारित होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए स्वस्थ समाज की संरचना करता है। यही सामाजिक समूह राष्ट्रीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान सुनिश्चित करता है।

वैसे यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति विचारधारा या मान्यता विशेष को लेकर बीते दौर से चली आ रही अवधारणा शत-प्रतिशत सही ही हो। बहुत स्वाभाविक है कि हम नायक को खलनायक और खलनायक को नायक मान बैठे हो। वैसे इतिहास में लगभग हर एक तथ्य का भरपूर लेखा-जोखा है। लेकिन इतिहास को देखने की दृष्टि में ही आमूलचूल परिवर्तन होने लगा है। तर्क के आधार पर किसी अवधारणा की सत्यता पर बल देना एक अलग बात है और कुतर्क के आधार पर दूध में नींबू निचोड़ने का उपक्रम एक अलग बात है। दोनों ही स्थिति में तटस्थ दृष्टिकोण ही किसी नतीजे पर पहुंचा सकता है।

दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जो अपने अपने हिसाब से ऐतिहासिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक पक्ष एक धारणा रखता है और दूसरा पक्ष दूसरी धारणा रखता है, अनावश्यक रूप से टकराव के आसार बनने लगते हैं। इन दिनों दौर ही ऐसा आ गया है कि किसी भी तथ्य पर विश्वास कर बैठने पर एक समय ऐसा भी आता है जब कि उस विश्वास के खंडित होने के आसार बन जाते है। ऐसे में चाहे किसी व्यक्ति या विचारधारा विशेष के बारे में कोई अवधारणा कितनी भी तथ्यपरक हो, तो भी कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर सवाल उठा दिया जाता है। इसके चलते जनमानस भ्रमजाल के भंवर में उलझ कर रह जाता है।

अनेक अवसरों पर ऐसे हालात बनने पर किसी समय की सर्वमान्य शख्सियत की छवि भी विवादास्पद बनती दिखाई देती है। तकनीकी संचार क्रांति के दौर में मिथ्या प्रचार का सिलसिला जोरों पर है। हर किसी प्रामाणिक मुद्दे पर भी तमाम तरह के किंतु परंतु उछाल कर आम आदमी के अंतर्मन में संदेह के बीच अंकुरित किए जा सकते हैं। इसका नतीजा यह होने लगा है कि किसी एक समय के महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का मूल्यांकन भी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर किया जाने लगा है। इसके चलते देशकाल और परिस्थिति का बिना खयाल रखें उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा है।

यह स्थिति एक-एक करके अनेक विभूतियां के गलत तरीके से चरित्र चित्रण का कारण भी बन रही है। सचमुच जब आदमी के अंतर्मन में गहरे रूप से समाहित कोई अवधारणा खंडित होने लगती है, तब दृष्टि ही ऐसी हो जाती है कि अटल सत्य पर भी सहसा विश्वास नहीं होता। इस विभ्रम की स्थिति से बचने के लिए हर किसी मामले में सतही दृष्टिकोण ही वह एकमात्र उपाय है जिसके चलते काफी हद तक मन का सुकून हासिल किया जा सकता है। अन्यथा आज के दौर में कल के सही को गलत और गलत को सही ठहराया जाने के चलते इस बात पर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि भविष्य में आज के सही को गलत और गलत को सही नहीं ठहराया जाएगा।

श्रम विभाग ने सत्यापन और ई-केवाईसी को बताया वजह

907 आवेदन लंबित, समय पर नहीं मिल रहा लाभ

बैतूल। जिले में संबल योजना प्रशासनिक सुस्ती और सत्यापन प्रक्रिया की खामियों का शिकार होती नजर आ रही है। ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद 900 से अधिक प्रकरण महीनों से लंबित हैं। नतीजा यह है कि जरूरतमंद श्रमिक परिवार योजना के तहत मिलने वाली प्रसूति सहायता, दुर्घटना एवं मृत्यु पर अनुग्रह राशि, शिक्षा प्रोत्साहन और अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। दरअसल संबल योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन आवेदन लंबित रहने से इसका सबसे अधिक नुकसान उन्हीं परिवारों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। प्रसूति सहायता, दुर्घटना या सामान्य मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक मदद, बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाओं का लाभ आवेदन स्वीकृत होने तक नहीं मिल पाता। डिजिटल संबल कार्ड भी आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही जारी होता है, जिससे अन्य योजनाओं में भी बाधा आती है। हितग्राहियों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो और श्रमिकों को समय पर उनका अधिकार मिल सके।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी योजना– असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना शुरू की थी। इस योजना में जन्म से लेकर मृत्यु तक और रोजगार से लेकर विवाह तक श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसमें पात्रता रखने वाले परिजनों को निर्धारित सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का

लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका संबल में पंजीयन और सत्यापन किया गया हो। संबल योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि की पात्रता निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, पेंटर, मिस्त्री, घरेलू कामकाजी महिला, ईंट-भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, सडक निर्माण से जुड़े, रिक्शा चालक, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों के अलावा विभिन्ना कामगारों को मिलती है। संबल योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन और भौतिक सत्यापन के बाद नियमों की पात्रता रखने पर राशि मिलती है।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन फिर भी सत्यापन की धीमी रफ्तार– संबल योजना में पंजीयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इसके बाद भी सत्यापन की रफ्तार धीमी है। श्रम विभाग लंबित आवेदनों के पीछे आधार ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन में आने वाली दिक्कतों को प्रमुख कारण बता रहा है। विभाग का कहना है कि कई हितग्राही मजदूरी के लिए जिले से बाहर चले जाते हैं और वहीं से आवेदन कर देते हैं। जब पंचायत सचिव या नगरीय निकाय के कर्मचारी भौतिक सत्यापन के लिए पहुंचते हैं तो संबंधित व्यक्ति घर पर नहीं मिलता, जिससे आवेदन लंबित रह जाते हैं। हालांकि हितग्राहियों का पक्ष इससे अलग है। उनका कहना है कि सत्यापन की जिम्मेदारी जिन पंचायत और नगरीय निकाय कर्मचारियों पर है, वे समय पर सत्यापन करने नहीं पहुंचते। कई मामलों में आवेदन करने के बाद भी लंबे समय तक कोई अधिकारी या कर्मचारी संपर्क नहीं करता। ऐसे में बिना किसी गलती के हितग्राहियों के आवेदन अधर में लटक जाते हैं और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता।

जनपद स्तर के आवेदन सबसे ज्यादा पेंडेंसी– जिले में नगरीय निकायों की अपेक्षा जनपद स्तर पर आवेदनों की पेंडेंसी अधिक है। जिले के जनपदों में करीब 823 आवेदन लंबित है, वहीं निकायों की स्थिति काफी बेहतर है। निकायों में योजनों के मात्र 84 आवेदन लंबित है। जनपद स्तर पर सबसे अधिक पेंडेंसी बैतूल और भैंसदेही जनपद में दर्ज की गई है। बैतूल जनपद में 145 तथा भैंसदेही में 121 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा चिचोली में 97, आमला में 89, भीमपुर में 82, प्रभातपट्टन में 79. शाहपुर में 75, घोड़ाडोंगरी में 71. मुलताई में 41 और आठनेर में 23 आवेदन स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। नगरीय निकायों में भी आवेदन लंबित हैं। बैतूल नगरपालिका में 19, शाहपुर में 22, घोड़ाडोंगरी में 15. मुलताई में 11. बैतूल बाजार में 6, सारनी और भैंसदेही में 5-5 तथा चिचोली में एक आवेदन लंबित बताया गया है।

संबल योजना व कितनी राशि देती है सरकार – जानकार बताते है कि संबल योजना के तहत मजदूर की दुर्घटना में मौत होने पर 4 लाख रुपये, सामान्य मौत पर 2 लाख, स्थाई अपंगता पर 2 लाख, आंशिक अपंगता पर एक लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपये की अनुग्रह राशि मिलती है। इसके साथ ही गर्भवती के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक जांच कराने और सरकारी अस्पताल में प्रसव होने पर सहायता राशि मिलती है। रोजगार के लिए पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को खुद के व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण भी दिया जाता है। मजदूर और उसके परिवार के सदस्य गंभीर बीमारियों में 2 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं।

इनका कहना है

संबल में पंजीयन के लिए लगातार आवेदन आते रहते हैं और इनका निराकरण भी किया जाता है। पुराने आवेदन पेंडिंग नहीं है। नए आवेदन है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जिले की स्थिति प्रदेश में बेहतर है।

– धम्म दीप भगत,
जिला श्रम अधिकारी बैतूल

उप मुख्यमंत्री ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार के विकास कार्यों की समीक्षा की

मुख्य मार्ग से गौवंश वन्य विहार तक बनेगी पीपल की छांव : पीपल के पौधों का होगा वृक्षारोपण

भोपाल । उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार पुर्वा के प्रशासनिक भवन में बैठक कर वन्य विहार की अधोसंरचना निर्माण, प्रबंधन, संचालन और परिसर में हो रही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का कार्य प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसलिए बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाए और इस कार्य में निरंतरता बनाए रखी जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन्य विहार परिसर में उत्पादित होने वाली प्राकृतिक सब्जियां, मूंग, चावल और गेहूं सहित सभी प्रकार की सामग्रियों की उचित ब्रांडिंग की जाए और बाजार में इनकी मार्केटिंग कराई जाए। प्राकृतिक खेती के प्रोडक्शन को रफ्तार देने के लिए नियमानुसार प्रोडक्शन मैनेजर और अन्य आवश्यक पदों पर सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया कराई जाए। बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने समिति बनाने के निर्देश दिए, जिसमें शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के सदस्यों को शामिल किए जाने के लिए कहा तथा इस समिति की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से आयोजित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बसामन गौवंश वन्य विहार में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए टीन शेड, पेवर ब्लॉक सहित अन्य सभी निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। गौ संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण की शुद्धता को बढ़ावा देने के लिए उपमुख्यमंत्री ने बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य मार्ग के मोड़ से लेकर बसामन मामा गौवंश वन्य विहार तक के पूरे रास्ते पर शीघ्र ही पीपल के पेड़ों का वृक्षारोपण कराया जाए। पीपल का पेड़ सर्वाधिक ऑक्सीजन देने और घनी छाया के लिए जाना जाता है, जिससे आने वाले समय में यह पूरा मार्ग हरा-भरा और पर्यावरण के अनुकूल नजर आएगा। उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि गौवंश की सेवा और पर्यावरण का संरक्षण, दोनों ही हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं। बसामन मामा वन्य विहार को एक आदर्श परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां हरियाली और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैठक में पूर्व विधायक श्री केपी त्रिपाठी, अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष राजेश यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, एसडीएम दृष्टि जायसवाल, एसडीओ फॉरेस्ट हितेश खंडेलवाल, डॉ. राजेश मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

प्राकृतिक खेती फसलों का अवलोकन कर सराहा

उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में भ्रमण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने परिसर में पूर्णतः प्राकृतिक रूप से उगाई गई सब्जियों को देखा। उन्होंने वहां उपजीं लौकी और तरोई जैसी प्राकृतिक सब्जियों की गुणवत्ता की सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिना रासायनिक खाद के तैयार की जा रही ये सब्जियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं।

विद्युत विभाग के संपर्क अभियान में 600 शिकायतें प्राप्त, 574 का मौके पर हुआ निराकरण

मीटर परिवर्तन, नए कनेक्शन, बिल संबंधी समस्याओं और विद्युत आपूर्ति की शिकायतों का शिविरों में हुआ समाधान

बैतूल / मुलताई। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के मुलताई संभाग द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सोमवार को संपर्क अभियान के तहत संभाग के सभी 10 वितरण केंद्रों के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने पहुंचकर बिजली बिल, मीटर, नए कनेक्शन तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। विभाग ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की। मुलताई संभाग के उपमहाप्रबंधक हितेश वशिष्ठ ने बताया कि सभी शिविरों में कुल 600 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 574 शिकायतों का तत्काल मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष शिकायतों का भी विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मीटर बदलने संबंधी 166 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और सभी 166 उपभोक्ताओं के मीटर तत्काल

बदल दिए गए। गलत बिजली बिल मिलने की केवल एक शिकायत दुनावा वितरण केंद्र से प्राप्त हुई, जिसका शिविर स्थल पर ही समाधान कर दिया गया। इसी प्रकार नए विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त 35 आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर ही कनेक्शन प्रदान किए गए। वहीं बिल प्राप्त नहीं होने संबंधी 96 शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को तुरंत डुप्लीकेट बिजली बिल उपलब्ध कराए गए। शिविर के दौरान 158 उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिलों का भुगतान भी किया। उपमहाप्रबंधक ने बताया कि विद्युत आपूर्ति एवं लो-वोल्टेज से संबंधित 75 शिकायतों का भी मौके पर निराकरण किया गया। उन्होंने कहा कि संपर्क अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके क्षेत्र में ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

9 से 11 जुलाई तक इन स्थानों पर लगेंगे अगले शिविर– उपमहाप्रबंधक हितेश वशिष्ठ ने बताया कि जुलाई माह में संपर्क अभियान के अगले चरण के तहत विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 9 जुलाई को वितरण केंद्र घाटबिरोली के ग्राम पिपरिया, साईखेड़ा के ग्राम निमनवाड़ा तथा दुनावा के ग्राम रिधोरा में शिविर लगाए जाएंगे। 10 जुलाई को वितरण केंद्र बिसनूर के ग्राम पंगमहू, रायआमला के ग्राम आष्टा, पट्टन के ग्राम बड़ली, जौलखेड़ा के ग्राम ऐनस तथा मुलताई ग्रामीण के ग्राम हतनापुर में शिविर आयोजित होंगे। वहीं 11 जुलाई को वितरण केंद्र मासोद के ग्राम इटावा तथा मुलताई शहर के इंदिरा गांधी वार्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उपमहाप्रबंधक श्री वशिष्ठ ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और बिजली से संबंधित अपनी समस्याओं का मौके पर ही समाधान प्राप्त करें।

भाजपा राज में मध्य प्रदेश बना शराब और ड्रग्स माफियाओं का सुरक्षित ठिकाना, मुख्यमंत्री जवाब दें : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने प्रदेश में लगातार सामने आ रहे शराब तस्करी और ड्रग्स के बड़े मामलों को भाजपा सरकार की कानून-व्यवस्था की पूरी तरह विफलता बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जवाब मांगा है। श्री पटवारी ने कहा कि हाल ही में आलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र में कूरियर कंपनी के दो कंटेनरों से करीब रू. 2 करोड़ मूल्य की 2,004 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि एक कंटेनर से 930 पेटी और दूसरे से 1,074 पेटी शराब बरामद की गई, जिसे ड्राई स्टेट गुजरात भेजा जा रहा था। इस मामले में देवास के दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह केवल इस विशाल नेटवर्क की एक छोटी कड़ी है।

उन्होंने कहा कि यह घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भोपाल,मंदसौर के बाद अब मऊगंज में करोड़ों रुपये की ड्रग्स फैक्ट्री पकड़े जाने का मामला सामने आ गया। यह साबित करता है कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और इसकी जड़ें बेहद गहरी हो चुकी हैं। शराब माफिया हों या ड्रग्स माफिया, दोनों ही बेखौफ होकर अपना कारोबार चला रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध का बड़ा नेटवर्क है। सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपये की अवैध शराब प्रदेश की सड़कों पर खुलेआम कैसे दौड़ रही थी? करोड़ों की ड्रग्स फैक्ट्री किसके संरक्षण में संचालित हो रही थी? क्या सत्ता के संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत के बिना इतना बड़ा अवैध कारोबार संभव है?

श्री पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दो दशक के शासन में मध्य प्रदेश अपराध और माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है। शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, रेत माफिया और भू-माफिया लगातार मजबूत हुए हैं। कानून का भय समाप्त हो चुका है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज प्रदेश का युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है, लेकिन सरकार केवल प्रचार और झूठे दावों में व्यस्त है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुशासन की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके शासन में मध्य प्रदेश शराब और ड्रग्स तस्करों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बन गया है। एक ओर ड्राई स्टेट गुजरात तक अवैध शराब पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के भीतर करोड़ों रुपये का ड्रग्स कारोबार फल-फूल रहा है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।

श्री पटवारी ने मांग की कि आलीराजपुर शराब तस्करी और मऊगंज ड्रग्स फैक्ट्री दोनों मामलों की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। केवल छोटे आरोपियों की गिरफ्तारी से सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। पूरे नेटवर्क के सरगनाओं, आर्थिक मददगारों, संरक्षण देने वाले अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

संगठनात्मक बैठक जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीति शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई, मूंग खरीदी मात्रा बढ़ाने की मांग

सोहागपुर। सोहागपुर विधायक विजयपालसिंह कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्यसमिति की बैठक जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर श्रीमति प्रीति शुक्ला ने कार्यकताओं संबोधित करते कहा कि आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों प्रदान की जाएगी। आपने आगे कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संगठन की रीति-नीति को जन-जन तक पहुंचाने तथा आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।संगठनात्मक बैठक के उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं एवं ब्लाक भाजपा अध्यक्ष अश्विनी सरोज ने किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों मूंग खरीदी का मामला जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला के समक्ष रखा। अश्विनी सरोज ने कहा कि वर्तमान में खाद की उपलब्धता एवं मूंग खरीदी में प्रति

एकड़ निर्धारित रखवा कम होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे किसानों में नाराजगी देखी जा रही है।इस गंभीर मुद्दे को शासन के समझ उठाएं । जिसमें प्रति एकड़ मूंग खरीदी की निर्धारित सीमा को बढ़ाया जाए। इससे वास्तविक उत्पादन करने वाले किसानों को राहत मिल सके। वर्तमान में किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हैं। इसके साथ ही खरीदी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इस कारण किसानों की समस्याओं को गंभीरता से उठाना संगठन की जिम्मेदारी है। इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं एवं मांगों को प्रदेश नेतृत्व और संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा । जिसका शीघ्र समाधान कराने का हरसंभव प्रयास किए जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि किसान खुशहाल रहे। इस अवसर कई वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आभार पार्षद आशीष विश्वकर्मा मालवीय ने व्यक्त किया।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रभारी अर्चना साहू, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल, वरिष्ठ वकील जयप्रकाश माहेश्वरी,मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज, नगर परिषद उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, जिला मंत्री श्रीमती पुष्पा वर्मा, जिला उपाध्यक्ष भगवान पटेल, जिला उपाध्यक्ष अभिनव पालीवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, महामंत्री मिथिलेश ठाकुर, ऋषभ गढ़वाल, एल्डरमैन नितिन कहार, पार्षद रविशंकर उईके, संजय मेहरा, रामकुमार ठाकुर, रामबाबू रघुवंशी, पवन चौधरी, रामाधार रघुवंशी, गोलू अग्रवाल,जगदीश अहिरवार, युगल रघुवंशी, रूपेश रघुवंशी, तरुण पथरिया, त्रिवेंद्र कुशवाहा, कमलेश कहार, डालचंद साहू, ललित बिश्नोई सहित नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उक्त आश्य की जानकारी युवा भाजपा नेता अभिनव पालीवाल ने इस प्रतिनिधि को दी।

संक्षिप्त समाचार

धनवाड़ा में माचक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे तीन लोगों को सुरक्षित निकाला

हरदा (निप्र)। लगातार हो रही बारिश के कारण धनवाड़ा क्षेत्र में माचक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से तीन लोग नदी के बीच स्थित घर एवं पेड़ पर फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री जयसिंह पिता अजबसिंह, श्री रूपचंद पिता टीकाराम एवं श्री गणेश पिता शिवप्रसाद नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बीच में स्थित घर एवं पेड़ पर फंस गए थे। सूचना मिलते ही एसडीएम खिरकिया सुश्री शिवांगी बघेल, तहसीलदार श्रीमती लवीना घाघरे तथा एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने त्वरित एवं सुनियोजित रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वर्षा ऋतु के दौरान नदी-नालों के समीप जाने अथवा जलभराव वाले क्षेत्रों को पार करने का प्रयास न करें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचना दें तथा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

ढाकनी-मुगली मार्ग पर जलभराव

जिला प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित मार्ग अपनाने की अपील

सीहोर (निप्र)। लगातार हो रही वर्षा के कारण सीहोर जिले के ढाकनी-मुगली मार्ग पर पापनास नदी स्थित पुल पर पानी का बहाव बना हुआ है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा दोनों ओर कोटवार एवं पुलिस दल की तैनाती की गई है, ताकि आवागमन पर सतत निगरानी रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में जलभराव वाले पुल, पुलिया अथवा तेज बहाव वाले स्थानों को पार करने का प्रयास न करें। थोड़ी-सी लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। नागरिक केवल सुरक्षित एवं वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें तथा प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।

शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिरोंज में सीएलसी प्रवेश चरण शुरू

विदिशा (निप्र)। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिरोंज में सीएलसी (कॉलेज लेवल काउंसलिंग) प्रवेश चरण प्रारंभ हो गया है। जिसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह प्रवेश का अंतिम सुनहरा अवसर है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिरोंज में सीएलसी राउंड के माध्यम से निम्न शाखाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश दिए जा रहे हैं जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी 04 जुलाई से 14 अगस्त 2026 के मध्य आवश्यक दस्तावेजों सहित महाविद्यालय पता पंडित दीन दयाल पार्क के पास सिरोंज में उपस्थित होकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र मो. 8319034281, 86304 77361 पर संपर्क करें।

लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश, ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने शनिवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विभिन्न राजस्व प्रकरणों एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने, राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने तथा आमजन को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिवेदन, प्रस्ताव एवं शासकीय रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही प्रेषित किए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ई-ऑफिस प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा प्रशासनिक कार्यों का त्वरित एवं सुव्यवस्थित निष्पादन सुनिश्चित होगा। उन्होंने अधिकारियों से इस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में भू-राजस्व, परिवर्तित भू-राजस्व, उपकर, शाला उपकर, प्रीमियम, भूभाटक सहित अन्य मदों की राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। साथ ही राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों, एसडीएम एवं तहसील न्यायालयों में लंबित मामलों, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा साइबर तहसील से जुड़े नामांतरण, तामीली और पटवारी रिपोर्ट की प्रगति पर चर्चा हुई।

बाढ़ तैयारी से लेकर खाद्य सुरक्षा तक हर मोर्चे पर अलर्ट रहें प्रशासन: कलेक्टर

कलेक्टर श्री गुप्ता ने राहत राशि वितरण, संभावित बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारियों, फार्मर आईडी, फसल गिरदावरी, वन व्यवस्थापन, वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावों के पुनः परीक्षण तथा वन राजस्व ग्रामों के समपरिवर्तन की समीक्षा भी की। इसके अलावा पीडीएस दुकानों की स्थिति, आयोग, जनशिकायत, सतर्कता, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, सीएम मॉनिट, सिविल सूट, सोलेशियम, शासकीय विभागों को भूमि आवंटन एवं आरआरसी प्रकरणों की प्रगति पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आयुष, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, मत्स्य, बिजली विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों को क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर होटल, दुकान एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करने तथा खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निरीक्षण और कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध वेतन काटने सहित कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले में कहीं भी नकली मावा की बिक्री नहीं होने पाए इसकी भी सघन जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही करते रहें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में आरटीओ विभाग को जिले में संचालित यात्री बसों, विशेषकर लंबी दूरी की बसों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों और आरटीओ को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बसों के सुरक्षा इंतजाम, परमिट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गाइडलाइन के अनुरूप जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले की शासकीय उचित मूल्य (पीडीएस) दुकानों के कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री गुप्ता ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रतिदिन निर्धारित समय पर खुलें का विशेष ध्यान रखें। इस संबंध में उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदार को भी समय-समय पर निरीक्षण भ्रमण कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। अनियमितताएं पाए जाने या दुकान समय पर नहीं खुलने के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बैठक में मूंग उड़द उपार्जन के कार्यों की भी समीक्षा की उन्होंने स्टॉल बुकिंग केन्द्रो की जानकारी प्राप्त करते हुए केन्द्रो की व्यवस्थाओं के संबंध में सभी एसडीएम को दिशा निर्देश दिए हैं।

वर्षाकाल में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारी रहें अलर्ट

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए बाढ़ आपदा पूर्व तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पहले से पूरी तरह सतर्क और तैयार रहें। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका रहती है, उनका चिन्हांकन कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित नागरिकों के सुरक्षित विस्थापन, अस्थायी आवास, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था पहले से कर ली जाएं। कलेक्टर ने पुल-पुलियों पर पानी भरने की स्थिति में तत्काल बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा किसी भी आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों के समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यानगत रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के माध्यम से सप्लाई होने वाले पानी की टेस्टिंग आवश्यक रूप से की जाए दूषित पानी सप्लाई न होने पाए इसका विशेष ध्यान रखें।

रपटों, पुलों और पुलियों पर पानी होने पर रास्ता पार न करें : कलेक्टर

वर्षा के दौरान नदी, तालाब, डेम एवं वॉटरफॉल के आसपास पिकनिक मनाने से बचें

सीहोर (निप्र)। वर्षा काल को देखते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा वर्षा के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें। उन्होंने नागरिकों से कहा है कि रपटों, पुलों एवं पुलियों पर पानी होने की स्थिति में रास्ता पार करने का प्रयास न करें। थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि वर्षा के दौरान नदी, नाले, तालाब, डेम, जलप्रपात (वॉटरफॉल) तथा अन्य जलस्रोतों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। इसलिए नागरिक ऐसे स्थानों पर पिकनिक मनाने अथवा घूमने जाने से बचें। उन्होंने अभिभावकों से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे बच्चों को नदी, तालाब, नालों एवं अन्य जलाशयों में नहाने या खेलने के लिए जाने से रोकें तथा उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखें। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों, नगर पालिका सीएमओ तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के नदी-नालों, तालाबों, डेमों, रपटों, पुल-पुलियों, वॉटरफॉल एवं जलभराव वाले क्षेत्रों की सतत निगरानी रखें। उन्होंने स्थानीय स्तर पर सतर्कता बनाए रखने, लोगों को समय पर सचेत करने तथा आवश्यकता पड़ने पर जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिलेवासियों से मौसम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने, तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन अथवा पुलिस को देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सावधानी ही सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है और सभी नागरिकों का सहयोग जन-धन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

वर्षा ऋतु में सुरक्षित पेयजल के लिए हैंडपंपों तथा पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन अभियान प्रारंभ

बैतूल (निप्र)। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी शासकीय हैंडपंपों तथा पेयजल स्रोतों का चरणबद्ध रूप से क्लोरीनेशन कराया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेयजल स्रोतों को पूर्णतः जीवाणुरहित रखते हुए ग्रामीण नागरिकों को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्षा ऋतु में भूजल एवं अन्य जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना रहती है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा नियमित रूप से हैंडपंपों तथा पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन एवं विसंक्रमण कराया जा रहा है, जिससे जलजनित रोगों जैसे डायरिया आदि की रोकथाम की जा सके तथा ग्रामीणों को गुणवत्तायुक्त पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। विभाग द्वारा जिले के 5 उप-खंडीय जल परीक्षण

प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। आमजन अपने क्षेत्र के पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए बैतूल प्रयोगशाला सुश्री ज्योति सरेयाम, सहायक यंत्री मो- 7974916270, भैंसदेही प्रयोगशाला श्री निखिल जैन, सहायक यंत्री मो- 8602617164, चिचोली प्रयोगशाला सुश्री वंदना उपराले, सहायक यंत्री मो- 9131146785, शाहपुर प्रयोगशाला श्री योगेश धुर्वे, सहायक यंत्री मो- 8458-868667, मुलताई प्रयोगशाला श्री संजीव नाखाते, सहायक यंत्री मो- 93020 36742 पर संपर्क कर सकते है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वर्षा ऋतु के दौरान जलजनित बीमारियों से बचाव पेयजल को हमेशा स्वच्छ, विसंक्रमित एवं ढक्कनदार बर्तनों में ही सुरक्षित रखे, पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले स्वच्छ बर्तन या करछी का उपयोग करें, सीधे हाथ पानी में न डालें, जनस्वास्थ्य की दृष्टि से, यदि संभव हो तो पेयजल को उबालकर एवं ठंडा करने के उपरांत ही उपयोग में लाएं। हैंडपंप एवं अन्य पेयजल स्रोतों के परिधि के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें तथा गंदा पानी जमा न होने दें। यदि किसी क्षेत्र में पेयजल दूषित , गंधयुक्त अथवा संदिग्ध प्रतीत होता है, तो उसका उपयोग तत्काल रोकें और उपरोक्त संबंधित उप-खंडीय प्रयोगशाला प्रभारी या विभागीय अधिकारियों को त्वरित सूचना दे।

जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर स्वैच्छिकता की शपथ लेकर किया पौधारोपण

सीहोर (निप्र)। जन अभियान परिषद द्वारा अपने स्थापना दिवस पर सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में स्वैच्छिकता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने समाज एवं राष्ट्रहित में निस्वार्थ भाव से कार्य करने का संकल्प लेते हुए स्वैच्छिकता की शपथ ली। इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक श्री प्रदीप सिंह सेंगर ने स्वैच्छिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के समग्र विकास में स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने जनभागीदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए सभी से सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

गोपालनगर स्कूल हादसे पर उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस, मांगा स्पष्टीकरण

विदिशा (निप्र)। विकासखंड सिरोंज के प्राथमिक/माध्यमिक शाला गोपालनगर में छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्रा के घायल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया ने जनपद शिक्षा केंद्र सिरोंज के उपयंत्री अनिल शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि तकनीकी दृष्टि से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना का कारण छत से पानी का रिसाव , वाटरप्रूफिंग कार्य का ठीक ढंग से नहीं होना तथा सरियों में जंग लग जाना रहा, जिसके कारण छत का प्लास्टर गिरा। विभाग के अनुसार खंड स्तर पर शाला भवनों के तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी उपयंत्री की होती है। ऐसे में नियमित निरीक्षण कर भवन की जर्जर स्थिति का आकलन करना तथा आवश्यकता होने पर कक्षाओं के संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि गोपालनगर विद्यालय में हुई घटना से स्पष्ट होता है कि संबंधित उपयंत्री तकनीकी पर्यवेक्षण के दायित्वों के निर्वहन में विफल रहे। साथ ही, संपर्क किए जाने पर वे यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि संबंधित विद्यालय भवन का निर्माण किस एजेंसी द्वारा कराया गया था।जिला शिक्षा केंद्र ने उपयंत्री अनिल शर्मा को निर्देश दिए हैं कि पत्र प्राप्त होने के दो दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण जिला शिक्षा केंद्र, विदिशा में प्रस्तुत करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी संविदा सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी।

शाला प्रभारी निलंबित

विद्यालय भवन के रखरखाव में लापरवाही के चलते सिरोंज विकासखंड के प्राथमिक शाला गोपालनगर में हुई दुर्घटना के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एक जुलाई को विद्यालय की छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्रा घायल हो गई थी। मामले की प्रारंभिक जांच में विद्यालय प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद संबंधित शाला प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्राथमिक जांच में पाया गया कि विद्यालय की छत से लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा था तथा वाटरप्रूफिंग का कार्य सही ढंग से नहीं कराया गया था। इसके कारण छत की सरियों में जंग लग गई और प्लास्टर कमजोर होकर गिर गया, जिससे यह हादसा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि शाला प्रभारी द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली शाला ग्रांट की राशि से भवन का आवश्यक रखरखाव नहीं कराया गया, जिसे दुर्घटना का प्रमुख कारण माना गया।

म.प्र. जन अभियान परिषद ने स्थापना दिवस पर स्वैच्छिकता पर्व का किया शुभारंभ

बैतूल (निप्र)। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के सभी दसों विकासखंडों में 'स्वैच्छिकता पर्व' का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 4 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य समाज में स्वैच्छिक सेवा, जनभागीदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त करना है। अभियान के शुभारंभ अवसर पर अधिकारियों, कर्मचारियों, नवांकुर संस्थाओं, प्रस्फुटन समितियों, सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राओं एवं परामर्शदाताओं, सीएम सोशल इंटर्न, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्वैच्छिकता शपथ ग्रहण कर समाजहित में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। स्वैच्छिकता पर्व के अंतर्गत जिलेभर में विभिन्न जनहितकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधरोपण, नशामुक्ति शपथ, स्वैच्छिकता शपथ, प्रेरक उद्बोधन, स्वच्छता अभियान, संस्कार केंद्रों में संगोष्ठियाँ तथा स्वैच्छिक भाव से कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं का सम्मान किया जाएगा। जिला समन्वयक संतोष सिंह राजपूत ने बताया कि यह अभियान समाज में सेवा, सहयोग एवं जनभागीदारी की संस्कृति को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने सभी नागरिकों, नवांकुर संस्थाओं, प्रस्फुटन समितियों, सामाजिक संगठनों तथा युवाओं से अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाकर समाजहित के कार्यों में अपना योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने स्वैच्छिक सेवा की भावना को जन-जन तक पहुँचाने तथा समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

युवाओं ने वृद्धाश्रम में बांटा अपनापन, वरिष्ठजनों की सेवा कर सीखे जीवन के मूल्य

मेरा युवा भारत, जिला विदिशा द्वारा श्री हरि वृद्धाश्रम में अनुभवात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

विदिशा (निप्र)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित मेरा युवा भारत , जिला विदिशा द्वारा समाज में सेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्री हरि वृद्धाश्रम, विदिशा में अनुभवात्मक प्रशिक्षण (एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम) का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, सहानुभूति और सेवा भाव से जोड़ते हुए उन्हें सामाजिक दायित्वों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान युवा स्वयंसेवकों ने वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के साथ आत्मीय समय बिताया। उन्होंने वरिष्ठजनों से संवाद कर उनके जीवन संघर्ष, अनुभव और मूल्यों को जाना तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त की। स्वयंसेवकों ने प्रेमपूर्वक भोजन परोसकर उनकी सेवा की, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा और उनके साथ बैठकर आत्मीय चर्चा की। इस दौरान मनोरंजक एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों का आयोजन भी किया गया, जिससे वृद्धजनों और युवाओं के बीच अपनत्व का भाव और अधिक प्रगाढ़ हुआ।

कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं ने समाज के प्रति अपने दायित्वों को निकट से समझा। वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों और मार्गदर्शन से उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सीखने का अवसर मिला। यह पहल पीढ़ियों के बीच संवाद को मजबूत करने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास साबित हुई। कार्यक्रम में स्वयंसेवक रोहन सैनी, विवेक नामदेव, शाश्वत जैन एवं लेखराज डांगी ने सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका निभाई। उनकी सेवा भावना और समर्पण की सभी ने प्रशंसा की।

इस अवसर पर मेरा युवा भारत, जिला विदिशा की उप निदेशक श्रीमती आकांक्षा महावेरिया, एमटीएस श्री ओमप्रकाश नामदेव, श्री हरि वृद्धाश्रम के प्रबंधक सहित आश्रम के अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने युवाओं के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, देखभाल एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। मेरा युवा भारत, जिला विदिशा ने भविष्य में भी समाज के विभिन्न वर्गों के हित में ऐसे जनकल्याणकारी एवं अनुभवात्मक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन जारी रखने का संकल्प दोहराया, ताकि युवाओं में सेवा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की भावना और अधिक सशक्त हो सके।

दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम

देश की प्राचीन मेधा को भावी पीढ़ी तक पहुँचाने का महायज्ञ : अपर मुख्य सचिव श्री शुक्ला

ज्ञान भारतम् ऐप पर मध्यप्रदेश ने अपलोड की सबसे अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सांस्कृतिक अभ्युदय के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की धरती ने भारत की प्राचीन ज्ञान-संपदा और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के विषय में देश भर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की डिजिटल पहल 'ज्ञान भारतम् ऐप' के अनुसार, दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। यह सफलता राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक पटल पर पुनः स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ज्ञान भारतम् ऐप के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश ने अब तक कुल 34 लाख 45 हजार 439 पांडुलिपियों पन्नों का पंजीकरण किया जा चुका है। 12 लाख 13 हजार 127 पांडुलिपियों का 'ज्ञान भारतम्' द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है शेष सत्यापन की प्रक्रिया में हैं, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है।

देश की प्राचीन मेधा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का महायज्ञ : अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला- अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा सामान्य प्रशासन श्री शिव शेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पाण्डुलिपियाँ हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण, डिजिटलीकरण और पुनर्प्रसार भारत की प्राचीन ज्ञान-संपदा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इसी के साथ भारत अपनी ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित करते हुए विश्व गुरु की अपनी गौरवशाली पहचान को सशक्त बना रहा है। मध्यप्रदेश के जिलों के उत्कृष्ट प्रयासों ने न केवल प्रदेश की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संरक्षण को नई दिशा दी है, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर को संरक्षित करने के राष्ट्रीय अभियान को भी मजबूती प्रदान की है।

प्रदेश में पांडुलिपियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान- ज्ञान भारतम् अभियान के अंतर्गत पांडुलिपियों के पंजीकरण में मध्यप्रदेश के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 जुलाई तक के आकंड़ों के अनुसार इनमें भोपाल ने सबसे अधिक 24 लाख 26, हजार 172 पांडुलिपियों का पंजीकरण किया है। इसके बाद इंदौर में 3,99,477, रीवा में 2,68,763, बैतूल में 1,00,593 तथा छिंदवाड़ा में 77,094 पांडुलिपियां दर्ज की गईं। पन्ना से 64,257, सागर से 60,025, ग्वालियर से 29,870, उज्जैन से 20,995, रायसेन से 15,539, मंदसौर से 12,412, अनूपपुर से 11,829, नीमच से 8,950, मऊगंज से 8,406, खंडवा से 5,740, जबलपुर से 4,715, सतना से 4,061, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) से 4,049, गुना से 3,937, उमरिया से 3,824, दतिया से 3,179, विदिशा से 2,745, सीधी से 2,497, अशोकनगर से 1,908, बालाघाट से 1,741, शहडोल से 1,397, टीकमगढ़ से 1,290, मंडला से 957, शिवपुरी से 943, धार से 870, भिंड से 800, रतलाम से 731, मुरैना से 655, शाजापुर से 638, बड़वानी से 614, सीहोर से 607, सिवनी से 564, छतरपुर से 381, देवास से 330, श्योपुर से 310, नरसिंहपुर से 254, राजगढ़ से 198, निवाड़ी से 177, खरगोन से 171, मैहर से 146, दमोह से 133, बुरहानपुर से 120, हरदा से 84, कटनी से 83, आगर मालवा से 57, सिंगरौली से 33, झाबुआ से 17, अलीराजपुर से 8, पांढुर्ना से 3 तथा डिंडोरी से 1 पांडुलिपि का पंजीकरण किया गया। यह व्यापक सहभागिता दर्शाती है कि प्रदेश के सभी जिलों ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण के राष्ट्रीय अभियान में अपनी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ज्ञान भारतम् ऐप और इसका उद्देश्य- ज्ञान भारतम् ऐप भारत सरकार की एक अनूठी डिजिटल पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखना और दुर्लभ पांडुलिपियों का एक विशाल डिजिटल अभिलेख (Digital Archive) तैयार करना है। ये भारतीय पांडुलिपियाँ केवल अतीत की स्मृतियाँ नहीं हैं, बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम् (विश्व एक परिवार है) की भावना से प्रेरित ज्ञान, संस्कृति और जीवन मूल्यों का जीवंत स्रोत हैं, जो संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस डिजिटल अभियान के माध्यम से शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए इन अमूल्य ग्रंथों तक पहुँच बेहद आसान हो गई है।

जिलों से मिलीं दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियाँ- ज्ञान भारतम् मिशन से हुए संरक्षण कार्य से कई प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों का पता चला है। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का रहस्यमयी नक्शा मिला है। इसमें प्राचीन भारतीय भूगोल को दर्शाने वाला जम्बूद्वीप का एक अत्यंत रहस्यमयी और दुर्लभ नक्शा अंकित है।चित्र में बीच में वृत्ताकार संरचना है, उसके चारों ओर पर्वत-मालाएं और क्षेत्र दिखाए गए हैं।

इसी तरह पन्ना से महाकवि केशव दास रचित रसिक प्रिया (1591 ई) की हस्त लिखित पांडुलिपि श्री राम जानकी मंदिर में मिली है। यह रीतिकाल का एक प्रतिष्ठित लक्षण-ग्रंथ है जो काव्यशास्त्र, श्रृंगार रस और नायिका-भेद पर आधारित है। इसमें अमूर्त शास्त्रीय नियमों को राधा-कृष्ण के प्रेम प्रसंगों और मौलिक छंदों के माध्यम से समझाया गया है। बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित 20 फीट लंबा प्राचीन श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ भी शामिल है, जिसका आधिकारिक तौर पर पंजीयन कर लिया गया है। दतिया के श्री राधा वल्लभ मिश्रा के आवास से ओरछा नरेश राजा उद्दोत सिंह के समय का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस पर विक्रम संवत 1828 अंकित है।

पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में नागरिक भी बन सकते हैं भागीदार

ज्ञान भारतम् ऐप न केवल सूचना देता है, बल्कि आम जनता को भी इस सांस्कृतिक महायज्ञ से जोड़ता है। स्मार्ट सर्चः उपयोगकर्ता शीर्षक, लेखक, भाषा, विषय और संग्रह स्थल के आधार पर किसी भी पांडुलिपि की जानकारी आसानी से खोज सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास कोई दुर्लभ पांडुलिपि उपलब्ध है, तो वे ऐप के माध्यम से उसके संरक्षण या डिजिटलीकरण के लिए सीधे अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। आम नागरिक अपने पास मौजूद प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी साझा कर भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की।

क्रेशर खदान में डूबने से भाई-बहन और बुआ की मौत

गेंद निकालने गए थे बच्चे ; बचाने के लिए कूदी बुआ, गहराई में समाए तीनों

ब्यावरा, राजगढ़ (नप्र)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में क्रेशर की खदान में डूबने से भाई-बहन और उनकी बुआ की मौत हो गई। बच्चे खदान में डूब रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए उनकी बुआ कूद गईं। इस दौरान बुआ भी गहराई में समा गईं। हादसा ब्यावरा के जगनियापुरा गांव में हुआ। जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे हुआ। मृतकों की पहचान निखरा पारदी (5), नम्रता पारदी (11) और सायराबाई पारदी (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जगनियापुरा के पास स्थित एक स्टोन क्रेशर मशीन की गहरी पानी से भरी खदान के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल के दौरान उनकी गेंद खदान में जा गिरी। गेंद निकालने के लिए निखरा पारदी और उसकी बहन नम्रता पारदी खदान के किनारे पहुंचे।

बच्चों की चीख सुनकर दौड़ी बुआ- दोनों जैसे ही गेंद निकालने का प्रयास करने लगे, अचानक उनका पैर फिसल गया। वे गहरे पानी में गिरकर डूबने लगे। दोनों बच्चों की चीख-पुकार सुनते ही उनकी 35 वर्षीय बुआ सायराबाई पारदी मौके पर पहुंचीं। बच्चों को डूबता देख उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए खदान में छलांग लगा दी। सायराबाई ने एक बच्चे को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन दूसरे बच्चे को बचाने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया।

खदान की गहराई में खुद को संभाल नहीं पाई बुआ

इस दौरान खदान की गहराई और पानी के कारण वे भी खुद को संभाल नहीं सकीं। देखते ही देखते तीनों पानी में समा गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे। तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद ब्यावरा सिटी थाना पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया।

एक घंटे चला रेस्क्यू, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर खदान में रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। इसके बाद सभी को तत्काल सिविल अस्पताल ब्यावरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए

ब्यावरा सिटी थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि खदान में डूबने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों शव परिजन को सौंप दिए गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बोलेरो-ट्रक की टक्कर से 5 की मौत, 4 गंभीर

गाड़ी में फंसे रहे शव, 3 लोग दूर जाकर गिरे, राजगढ़ से आष्टा जा रहे थे

आष्टा (नप्र)। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ट्रक और बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बोलेरो में सवार अंदर फंस गए, जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, हादसा सोमवार दोपहर करीब 2:45 बजे आष्टा और शुजालपुर के बीच ग्राम मेना गोदी के पास हुआ। 3 लोग बोलेरो से उछलकर 15-20 फीट दूर गिरे, जबकि ड्राइवर की खून से सनी लाश गाड़ी में फंसी रही। हादसे में 2 लोगों के पैर टूट गए, जबकि अन्य के सिर में गंभीर चोटें आईं।

सभी राजगढ़ के कालीपीठ क्षेत्र के रहने वाले- आष्टा एसडीओपी दामोदर गुप्ता ने बताया कि सभी लोग राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र के भियापुरा गांव के रहने वाले हैं। वे इलाज कराने आष्टा जा रहे थे। आष्टा-पचोर-शुजालपुर मार्ग पर मेना गोदी गांव के पास हादसे का शिकार हो गए।

आष्टा एसडीओपी दामोदर गुप्ता ने बताया कि बोलेरो में 9 लोग सवार थे। इनमें राजाराम सुंदर (45), भगवान (50), इंदर सिंह (55), राधेश्याम (38), बनेसिंह (22), गुलाबचंद (30), हेमराज (25), देवीराम (60) और अमरसिंह (45) शामिल थे।

ग्रामीणों और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू- हादसे की सूचना मिलते ही आष्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने क्षतिग्रस्त बोलेरो में फंसे घायलों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उन्हें सिविल अस्पताल आष्टा पहुंचाया गया। वहां से सीहोर जिला अस्पताल रेफर किया गया। गंभीर हालत होने पर भोपाल भेज दिया गया।

शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए- पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए। अब तक सिर्फ 2 घायलों की पहचान इंदर सिंह पिता नंदराम और राजाराम पिता गणपत के रूप में हो पाई है। मृतकों की पहचान के लिए पुलिस जानकारी जुटा रही है।

मऊगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता

मकान में तैयार हो रही थी करोड़ों की एमडी ड्रग्स, चार गिरफ्तार

मऊगंज (नप्र)। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस ने नशे के साम्राज्य पर ऐसा प्रहार किया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। किराए के एक मकान में महीनों से मौत का कारोबार चल रहा था, जहां करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। मऊगंज पुलिस ने पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया है।

एक करोड़ से ज्यादा का माल बरामद- छापेमारी के दौरान यहां एक करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। साथ ही करोड़ों का केमिकल, हाईटेक लैब, मशीनें और तस्करी में इस्तेमाल होने वाला वाहन मिला है। पुलिस ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे नेटवर्क के पीछे बैठे बड़े तस्करों की तलाश की जा रही है।

अब तक की है सबसे बड़ी कार्रवाई- नशे के सौदागरों के खिलाफ मध्य प्रदेश के मऊगंज पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बिझौली गांव के एक किराए के मकान में ड्रग्स का निर्माण चल रहा था। मकान दिखने में बिल्कुल साधारण था। पुलिस की टीम मकान के अंदर पहुंची तो नजारा देखकर अंदर के लोग हैरान रह गए। जांच में सामने आया कि यह अवैध फैक्ट्री मार्च महीने से लगातार संचालित हो रही थी और यहां बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ तैयार किए जा रहे थे।

मौके से मिले हैं ये सामान- कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 360 ग्राम संदिग्ध एमडी ड्रग्स बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा 300 लीटर से अधिक रासायनिक पदार्थ, भारी मात्रा में कच्चा माल, ओवन मशीन, वैक्यूम पंप, हीटर, जनरेटर सहित ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई आधुनिक उपकरण जब्त किए गए। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बोलेरो गाड़ी भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपये आंकी गई है।

चार लोग मौके से गिरफ्तार- पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें चंदन सिंह, अशोक गुप्ता और पीयूषचंद्र यादव गढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि चौथा आरोपी ऋषभ सेन गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर पुलिस अब इस पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है।

महीनों से चल रही थी संदिग्ध गतिविधियां

ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले कई महीनों से इस मकान में संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। देर रात लग्जरी और मालवाहक गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता था। आसपास के लोगों को केमिकल की तेज बदबू आती थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि गांव में मौत की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ इस अवैध फैक्ट्री को बंद कराया, बल्कि इलाके में फैले ड्रग्स नेटवर्क को भी बड़ा झटका दिया है।

कहां होती थी सप्लाई

शाहपुर थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह ड्रग्स किन-किन राज्यों तक सप्लाई की जा रही थी, इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इस पूरे रैकेट को आर्थिक मदद कौन दे रहा था। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े चेहरे भी कानून के शिकंजे में होंगे।

एसीएस का 'सुपर-अनुशासन'

विभाग में नए अपर मुख्य सचिव के आते ही हवा का रुख बदल गया है। जो बाबू कभी फाइल दबाकर चाय की चुस्कियाँ लेते थे, अब वे रिव्यू मीटिंग में ऐसे मुस्तैद दिखते हैं जैसे किसी युद्ध के लिए जा रहे हों। एसीएस की 'सख्ती' का असर यह है कि अब साहब के सामने बिना तैयारी जाने से पहले अधिकारियों के हाथ-पांव कांपने लगे हैं। वाकई, अनुशासन का डंडा चले तो सुस्ती भी फुर्ती में बदल जाती है!

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

आईपीएस की 'यू-टर्न' वाली जुगाड़

पुलिस मुख्यालय में एक आईपीएस अधिकारी की 'जादूगरी' पूरे विभाग में चर्चा का केंद्र है। साहब को सरकार ने लूप-लाइन में क्या भेजा, उन्होंने अपनी पहुंच के ऐसे तीर चलाए कि चंद महीनों में फिर मुख्यालय में मलाईदार पोस्टिंग पा ली। पर चर्चा यह है कि साहब का मन अब यहाँ भी नहीं टिक रहा। सुना है, नई 'जुगाड़' की तलाश शुरू हो चुकी है, आखिर दबंगई और कुर्सी का साथ जो पुराना है!

मैडम का 'स्ट्रेट-फॉरवर्ड' तड़का

एक बड़े विभाग में मंत्री जी और महिला प्रशासनिक प्रमुख की 'ट्यूनिंग' इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। मंत्री जी सिफारिशों की फाइलें भेजकर थक गए, लेकिन मैडम हैं कि फाइलें 'डिब्बा बंद' होने से बच ही नहीं रही हैं। मंत्री जी बेचारे असहज हैं, क्योंकि मैडम के दरबार में 'किंतु-परंतु' की कोई जगह नहीं। अब देखना ये है कि कौन पहले झुकता है—मंत्री की सिफारिश या मैडम का 'स्ट्रेट-फॉरवर्ड' नियम?

तबादलों में 'दलाल' हुए बेरोजगार

जिस विभाग में कभी 'तबादला उद्योग' का सिक्का चलता था, वहां इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। करीब 10 हज़ार तबादले हुए, लेकिन दलालों को एक चवन्नी भी नहीं मिली! 9 हज़ार 200 तबादले ऑनलाइन और विकल्प आधारित रहे। जो 800 प्रशासनिक थे, उनमें ही थोड़े-बहुत सियासी 'तड़के' दिखे। बाकी पूरा विभाग इस पारदर्शी नीति से हैरान है और मंत्री-मुखिया की तारीफ के पुल बांध रहा है।

दतिया विधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में आज मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दतिया जिला प्रशासन की बैठक ली।